हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - CTHIN/25/A0716

मूक पत्रिका

निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष - 02 अंक - 337 बेमेतरा, सोमवार 03 अगस्त 2026 रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित कुल पेज - 08 मूल्य - 1 रूपये डाक पंजीयन- दुर्ग/1743290201/2025-27

नए आपराधिक कानूनों ने न्याय व्यवस्था में लाया ऐतिहासिक परिवर्तन : सीएम साय

रायपुर। वर्तमान समय की आवश्यकताओं और बदलती चुनौतियों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए नए आपराधिक कानून भारत की न्याय व्यवस्था में ऐतिहासिक परिवर्तन के वाहक बने हैं। इन कानूनों का उद्देश्य केवल अपराधियों को दंडित करना नहीं, बल्कि आम नागरिक को त्वरित, पारदर्शी, सुलभ और समयबद्ध न्याय उपलब्ध कराना है।

आधुनिक तकनीक, डिजिटल प्रणालियों और वैज्ञानिक साक्ष्यों को न्याय प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा बनाकर न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी, विश्वसनीय और जवाबदेह बनाया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर में आयोजित स्ट्रेंथिंग डिजिटल जस्टिस राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगभग डेढ़ सौ वर्ष पुराने औपनिवेशिक कानूनों के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किए गए हैं। इन कानूनों की मूल भावना नागरिक-केंद्रित न्याय व्यवस्था की स्थापना है, जिसमें पीड़ित को शीघ्र न्याय मिले और अपराधी कानून के शिकंजे से बच न सके। उन्होंने कहा कि पुराने कानून ऐसे समय में बने थे, जब डिजिटल तकनीक, सीसीटीवी, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और आधुनिक फॉरेंसिक विज्ञान का अस्तित्व नहीं था। अपराधों की प्रकृति बदल चुकी है और तकनीक

न्याय व्यवस्था का अनिवार्य हिस्सा बन गई है। नए कानूनों ने डिजिटल साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल चैट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तथा वैज्ञानिक फॉरेंसिक जांच को विधिक मान्यता देकर अपराध अनुसंधान और अभियोजन को नई मजबूती प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की शाखा प्रारंभ होने से अपराध अनुसंधान और न्यायिक प्रक्रिया को नई दिशा मिलेगी। ई-साक्ष्य जैसी व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के सुरक्षित संरक्षण और उनकी प्रामाणिकता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि डिजिटल तकनीक के उपयोग से न्याय प्रक्रिया पहले की तुलना में कहीं अधिक तेज और प्रभावी हुई है। पहले समन की तामील में कई दिन लग जाते थे, जबकि अब ई-समन के माध्यम से सूचना तत्काल संबंधित व्यक्ति तक पहुंच रही है और उसकी डिजिटल ट्रैकिंग भी संभव हो गई है। न्याय श्रुति जैसी व्यवस्था न्यायालयीन कार्यवाही के सुरक्षित डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने के साथ-साथ ऑनलाइन एवं हाइब्रिड सुनवाई को भी अधिक सक्षम बना रही है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (सीसीटीएनएस) के माध्यम से देशभर के पुलिस थाने डिजिटल रूप से एक-दूसरे से जुड़े हैं। इससे अपराधियों का रिकॉर्ड तत्काल उपलब्ध हो जाता है और पुलिस को त्वरित कार्रवाई में सुविधा मिलती है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के सभी थाने ऑनलाइन मोड में कार्यरत हैं तथा राज्य में अब तक 1 लाख 97 हजार 547 एफआईआर ऑनलाइन दर्ज की जा चुकी हैं। नागरिकों को डिजिटल हस्ताक्षरित एफआईआर की प्रति भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) न्यायपालिका, पुलिस, अभियोजन, जेल और अन्य संबंधित संस्थाओं के बीच सुरक्षित डिजिटल समन्वय स्थापित कर रहा है। इससे सूचनाओं का त्वरित आदान-प्रदान संभव हुआ है और न्यायिक प्रक्रिया में होने वाली अनावश्यक देरी में उल्लेखनीय कमी आई है। उन्होंने कहा कि नए कानूनों से न्याय प्राप्त करने की प्रक्रिया पहले की अपेक्षा अधिक सरल, पारदर्शी और कम खर्चीली हुई है।

नए कानूनों और डिजिटल न्याय प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ बनेगा देश का अग्रणी राज्य : न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने कहा कि तीनों नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य की आपराधिक न्याय प्रणाली अधिक पारदर्शी, वैज्ञानिक, त्वरित और तकनीक आधारित बनेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम देश की न्याय व्यवस्था में व्यापक बदलाव लेकर आए हैं। इन कानूनों की सफलता केवल उनके लागू होने में नहीं, बल्कि सभी संबंधित संस्थाओं द्वारा उनके प्रभावी क्रियान्वयन में निहित है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आज की चर्चा केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपराधिक अनुसंधान और न्यायिक प्रक्रिया में व्यापक परिवर्तन का प्रतीक है। ई-साक्ष्य, ई-चालान, न्याय श्रुति तथा डिजिटल फॉरेंसिक्स जैसी व्यवस्थाएं नए कानूनों की मूल भावना को साकार करने के महत्वपूर्ण माध्यम हैं। विशेष रूप से ई-साक्ष्य को उन्होंने साक्ष्य प्रबंधन की समग्र एवं एकीकृत प्रणाली बताते हुए कहा कि इससे साक्ष्यों की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि न्याय की प्रक्रिया अपराध स्थल से प्रारंभ होती है।

नये आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन में डिजिटल तकनीक की भूमिका महत्वपूर्ण : विजय शर्मा

गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि नये आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन में डिजिटल तकनीक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है और इसी उद्देश्य से इस राज्यस्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। नवीन आपराधिक कानूनों के माध्यम से डिजिटल न्याय व्यवस्था को सशक्त बनाना' विषय पर राज्यस्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में गृह विभाग, न्यायपालिका, अभियोजन, फॉरेंसिक विभाग तथा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अधिकारियों ने भाग लिया। इस मौके पर शर्मा ने कहा कि कि राज्य सरकार पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की दिशा में कार्य कर रही है उन्होंने बताया कि प्रदेश में सीसीटीएनएस, ई-साक्ष्य तथा न्याय श्रुति जैसी डिजिटल व्यवस्थाएं पहले से संचालित हैं। अब इन सभी प्रणालियों को आपस में जोड़कर पुलिस, अभियोजन, फॉरेंसिक और न्यायपालिका के बीच समन्वय को और अधिक मजबूत किया जाएगा। इससे न्यायिक प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, त्वरित और प्रभावी बनेगी।

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: अवैध शराब परिवहन में प्रयुक्त ट्रक, ऑडिट फर्म से दस्तावेज एवं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले की जांच कर रही आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जांच के सिलसिले में एक और महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए लॉकडाउन अवधि में कथित तौर पर अवैध शराब के परिवहन में इस्तेमाल किए गए ट्रक को जब्त कर लिया है।

जांच एजेंसी से रविवार को प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह ट्रक एक उद्योग के नाम पर पंजीकृत है जिसका प्रोपराइटर मित्तल नामक कारोबारी हैं।

एजेंसी का दावा है कि अनवर ढेबर के निर्देश पर इसी वाहन के जरिए एमवी डिस्टलरीज से शराब विभिन्न होटलों और बार तक पहुंचाई गई थी। जांच एजेंसी ने बताया कि जांच के दौरान पूछताछ में यह तथ्य सामने आया कि मार्च और अप्रैल 2020 के लॉकडाउन के दौरान एमवी डिस्टलरीज से लगभग 8,400 पेटी शराब का अवैध परिवहन और विक्रय किया गया।

एजेंसी का आरोप है कि पूरे नेटवर्क का संचालन अनवर ढेबर के निर्देश पर किया गया। इसी क्रम में एक अगस्त 2026 को उक्त ट्रक को जब्त किया गया। जांच एजेंसी के अनुसार, अब तक इस मामले में 24 वाहनों की जब्ती की जा चुकी है। जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि लॉकडाउन के दौरान निम्न गुणवत्ता की शराब का निर्माण किया गया था, जिसे बाद में पीने योग्य नहीं बताते हुए नष्ट कर दिया गया। एजेंसी ने बताया कि कुछ अन्य वाहनों के उपयोग की भी जानकारी मिली है। इनमें से कई वाहन बेचे जा चुके हैं अथवा अन्य कार्यों में इस्तेमाल हो रहे हैं। ऐसे वाहनों के स्वामित्व और उपयोग की अलग से जांच की जा रही है। इस बीच जांच एजेंसी ने छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से नियुक्त नोडल ऑडिट फर्म पीएसएसी एंड एसोसिएट्स के मोतीलाल नेहरू नगर (पूर्व), भिलाई स्थित कार्यालय में भी तलाशी अभियान चलाया।

कार्रवाई के दौरान ऑडिट से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए गए। ईओडब्ल्यू का कहना है कि ऑडिट के दौरान कई शराब दुकानों की जांच नहीं होने दी गई, जिससे कथित अवैध शराब बिक्री के नेटवर्क पर प्रभाव नहीं पड़े। एजेंसी ने कहा कि मामले में आगे की जांच और वैधानिक कार्रवाई जारी है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी कर रहा है।

ईडी की शिकायत पर एसीबी में दर्ज प्राथमिकी में 2,000 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले का उल्लेख किया गया है।

दक्षिणी पेरू में विमान दुर्घटना में 13 लोगों की मौत

लीमा। दक्षिणी पेरू में नाज़्का जियोग्लिफ्स वाले पुरातात्विक स्थल के ऊपर एक छोटे पर्यटक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 13 लोगों की मौत हो गई। यह जानकारी स्थानीय प्रसारक टीवी पेरू ने अपनी रिपोर्ट में दी।

आरपीपी रेडियो की एक रिपोर्ट के अनुलाप, मारे गए 13 लोगों में से 11 विदेशी पर्यटक थे, जिनमें सात इटैलियन, दो जर्मन और दो स्पैनिश नागरिक शामिल थे और बाकी दो लोग विमान के क्रू मेंबर थे पेरू के रहने वाले थे। दुर्घटना के कारण का अभी तक पता नहीं चला है।

विमान के क्रू ने अलार्म बजाया, उसके बाद संपर्क समाप्त हो गया। विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद आग लग गई। जब बचाव टीम मौके पर पहुंची, तो उन्होंने केवल यह पुष्टि की कि विमान में सवार सभी की मौत हो गई थी।

प्रधानमंत्री के आह्वान पर अरुणाचल ने शुरू किया 100 दिवसीय नशा विरोधी जागरूकता अभियान

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वर्चुअली शुरू किये गये देशव्यापी 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान' में भाग लेते हुए अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) केटी परनाइक ने रविवार को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ एक निरंतर और जन-संचालित अभियान चलाने का आह्वान किया। राज्यपाल ने यहां लोक भवन से प्रधानमंत्री के 100 सप्ताह के देशव्यापी जन भागीदारी अभियान का शुभारंभ करते हुए इस वर्चुअल बातचीत में अरुणाचल प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों और युवा केंद्रों सहित देशभर के 10,000

से अधिक स्थानों से एक करोड़ से अधिक युवाओं को संबोधित किया गया। इस अभियान का उद्देश्य मादक पदार्थों के सेवन के खिलाफ लड़ाई में युवाओं और समुदायों को एकजुट करना है और 'विकसित भारत 2047' के आवश्यक स्तंभ के रूप में नशा मुक्त भारत के दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। राज्यपाल ने वर्चुअल कार्यक्रम के बाद अधिकारियों से चर्चा की और विशेष रूप से युवाओं के बीच जागरूकता फैलाने एवं सक्रिय जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए पूरे राज्य में अगले 100 दिनों तक हर रविवार को 'नशा मुक्त नुक्कड़ कार्यक्रम' आयोजित करने का प्रस्ताव रखा।

नशीली दवाओं के खिलाफ लड़ाई को जमीनी स्तर से शुरू करने पर जोर देते हुए राज्यपाल ने 'पता लगायें-सलाह दें-रोकें-कौशल' दृष्टिकोण की वकालत की।

चढ़ावा चोरी की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी करे जांच : प्रमोद तिवारी

नयी दिल्ली। कांग्रेस ने अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में विशेष जांच दल (एसआईटी) से व्यापक एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

पार्टी का कहना है कि राम मंदिर से जुड़े पदाधिकारियों की नियुक्ति ट्रस्ट की बजाय भाजपा के इशारे पर हुई है और चढ़ावा चोरी का खुलासा होने के बाद इस्तीफे देना इस पूरे मामले की गंभीरता को दर्शाते हैं इसलिए पूरे प्रकरण की इसकी निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी ने रविवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि अयोध्या में भूमि अधिग्रहण से लेकर मंदिर निर्माण और चढ़ावे के प्रबंधन तक लगातार कई गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर ट्रस्ट ने सात भूखंडों की खरीद की है और वे भूखंड राम मंदिर से काफी दूर हैं। इन भूखंडों का मंदिर के लिए कोई उपयोग नहीं है ऐसे में इन खरीदों का उद्देश्य स्पष्ट किया जाना चाहिए। तिवारी ने कहा, राम मंदिर में सिर्फ चढ़ावे की चोरी नहीं हुई, बल्कि शिला पूजन के समय से ही चोरी शुरू हो गई थी। उन्होंने कहा कि वह अवध क्षेत्र के रहने वाले हैं और वर्ष 1985 से 1990 के बीच उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्री रहे हैं। उनका दावा था कि उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को शुरू से बहुत करीब से देखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने मंदिर निर्माण से अधिक मंदिर आंदोलन का राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास किया।

उनका कहना यह भी कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर का उद्घाटन तब किया, जब निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ था। इसे परंपराओं के विपरीत बताते हुए उन्होंने दावा किया कि इसका राजनीतिक असर भी भाजपा पर नकारात्मक पड़ा है और उसकी लोकसभा की सीटें 306 से घटकर 240 पर आई हैं। कांग्रेस नेता ने मंदिर समिति द्वारा अनाप शनाप खर्च किए जाने का आरोप लगाया और कहा कि मंदिर उद्घाटन समारोह पर 112 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

यात्रा अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में रह रहे छह बंगलादेशी नागरिक हिरासत में

नयी दिल्ली। दिल्ली में छह बंगलादेशी नागरिकों को भारत में तय अवधि से अधिक समय तक रहने और वीज़ा के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में हिरासत में लिया गया है।

पुलिस ने रविवार को बताया कि यह कार्रवाई मध्य जिला पुलिस द्वारा चलाए गए 'ऑपरेशन विस्टा 1.0' के तहत की गई। इस अभियान का उद्देश्य वीज़ा की शर्तों का उल्लंघन करने वाले और वीज़ा की अवधि खत्म होने के बाद भी भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करना है।

पुलिस के अनुसार, पूरे मध्य जिला के अलग-अलग होटलों और गेस्ट हाउस में जांच और

सत्यापन का काम चलाया जा रहा था। इसी दौरान नबी करीम इलाके में आराकशां रोड पर स्थित एक होटल में जांच के दौरान ये छहों बंगलादेशी नागरिक ठहरे हुए मिले। पुलिस ने बताया कि जब उनके पासपोर्ट, वीज़ा और यात्रा से जुड़े दस्तावेजों की जांच की गई, तो पता चला कि ये छहों नागरिक 'डबल एंट्री वीज़ा' पर कानूनी तरीके से ही भारत आए थे। इस वीज़ा के तहत उन्हें हर यात्रा के दौरान ज्यादा से ज्यादा 15 दिनों तक भारत में रहने की छूट थी। हालांकि, उन्होंने वीज़ा की अवधि बढ़ाने के लिए कोई आवेदन नहीं किया और बिना किसी आधिकारिक अनुमति के तय समय से ज्यादा दिनों तक भारत में रुक गए। अधिकारियों ने बताया कि छहों लोगों को पकड़कर विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) के सामने पेश किया गया। वीज़ा नियमों के उल्लंघन के मामले में एफआरआरओ ने कानूनी कार्रवाई शुरू की और उनके खिलाफ प्रतिबंध आदेश जारी किए। इसके बाद सभी को वापस उनके देश भेजे जाने तक सराय रोहिल्ला स्थित 'सेवा धाम' निरुद्ध केंद्र (डिटेंशन सेंटर) भेज दिया गया है।

आठ गोदामों और एक अवैध विनिर्माण इकाई को जब्त किया

सीबीएन ने बिहार में नकली दवाओं के अंतर-राज्यीय नेटवर्क का किया भंडाफोड़ , सरगना गिरफ्तार

नयी दिल्ली। 'ऑपरेशन वज्र' के तहत, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) की मध्य प्रदेश इकाई ने बिहार के गया और मसौढ़ी (पटना) में नकली एवं अवैध दवाओं के आठ गोदामों और एक अवैध विनिर्माण इकाई को जब्त किया है।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में रविवार को बताया गया है कि गोदाम जैसी इन जगहों का इस्तेमाल मादक पदार्थों और अन्य दवाओं को अवैध रूप से बनाने और भंडारण करने के लिए किया जा रहा था। यह मामला 2025 में दर्ज अपराध की जांच से भी जुड़ा है और इसे इस जांच में एक और बड़ी कामयाबी बताया गया है।

ताजा अभियान के दौरान गया में चार अवैध गोदामों का भंडाफोड़ किया गया, जिसमें 68,200 ट्रामाडोल टैबलेट, 59,000 अन्य टैबलेट और कोडीन सिरप की 52,542 बोतलें जब्त की गईं।

लगातार जांच और तकनीकी व मानवीय खुफिया जानकारी जुटाने के आधार पर, सीबीएन ने 22 जुलाई को मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी से महत्वपूर्ण सुराग मिले, जिससे आगे बड़े पैमाने पर कार्रवाई का रास्ता साफ हुआ।

जांच के दौरान 16 से 27 जुलाई के बीच, सीबीएन की मध्य प्रदेश इकाई (नीमच) के निवारक अनुभाग ने पूरे बिहार में कड़ी निगरानी और क्षेत्रीय अभियान चलाए। जांच के दौरान पता चला कि फरार आरोपी ने गया के खानजहांपुर इलाके में गैर-कानूनी तरीके से बनाए गए नशीले पदार्थों और नकली दवाओं को जमा करने के लिए फिर से अवैध गोदाम चलाना शुरू कर दिया था। कई दिनों तक उसकी गतिविधियों पर गुप्त रूप से नजर रखने के बाद, सीबीएन की टीम ने उसे पकड़ा। आरोपी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर, सीबीएन की टीम ने दो अपंजीकृत और बिना मंजूरी वाले गोदामों की तलाशी ली और गैर-कानूनी तरीके से बनाए गए 21,373 ब्यूप्रेनोर्फिन इंजेक्शन एम्प्यूल बरामद किए। तलाशी के दौरान भारी मात्रा में नकली और मिलावटी गैर-एनडीपीएस दवाएं भी ज़ब्त की गईं, जिनमें क्लैवम-625, पैन-40, बेटाडीन ऑइंटमेंट, एजिथ्रल और कई अन्य दवाएं शामिल थीं। उसके बाद स्थानीय पुलिस की सहायता से किए चलाए गए अभियानों से शहर के विभिन्न हिस्सों में स्थित छह और अपंजीकृत और अनधिकृत गोदामों की पहचान की गई। इन परिसरों से पर्याप्त मात्रा में नकली और अनाधिकृत रूप से भंडार की गई गैर-एनडीपीएस दवाएं मिलीं। जब्त किए गए भंडार और सील किए गए गोदामों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए बिहार राज्य औषधि प्रशासन को सौंप दिया गया। सीबीएन द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर, राज्य औषधि विभाग ने अवैध गोदामों से बड़ी मात्रा में गैर-एनडीपीएस नकली दवाएं जब्त कीं इनमें टैबलेट/कैप्सूल 439,774, इंजेक्शन/वायल/एम्प्यूल1,895, सिरप/बोतलें 3,811और अन्य दवा उत्पाद (लोशन/ट्यूब/ड्रॉप्स, आदि) 3,490 शामिल हैं। लगातार पूछताछ के दौरान, संदिग्धों ने बताया कि उनके पहले गिरफ्तार किए गए एक साथी ने पटना के मसौढ़ी के पास एक फार्महाउस में गैर-कानूनी विनिर्माण इकाई बनाई थी, जहां बुप्रेनोरफिन और अन्य नशीले पदार्थों को गैर-कानूनी तरीके से बनाने के लिए मशीनरी और उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस जानकारी पर तुरंत कार्रवाई करते हुए, सीबीए की टीम ने स्थानीय पुलिस, राज्य औषधि विभाग और खाद्य विभाग के अधिकारियों की मदद से उस जगह पर संयुक्त तलाशी अभियान चलाया।

केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो
CENTRAL BUREAU OF NARCOTICS
सत्यमेव जयते

मॉस्को के एक रेस्तरां में विस्फोट तीन की मौत, 21 घायल

मॉस्को। रूस की राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी समिति (एनएसी) ने कहा है कि मॉस्को के एक रेस्तरां में शनिवार को हुआ विस्फोट बम धमाका था, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गयी और 21 अन्य घायल हो गये।

समिति ने सरकारी समाचार एजेंसी तास के हवाले से बताया कि मॉस्को के कुड्रिन्स्काया स्क्वायर स्थित एक रेस्तरां में देसी विस्फोटक उपकरण (आईईडी) में विस्फोट हुआ। मृतकों में विस्फोटक लेकर रेस्तरां में प्रवेश करने वाली एक महिला, उसे रोकने वाला एक सुरक्षा कर्मी तथा एक ग्राहक शामिल हैं। रूसी सुरक्षा एजेंसियों से करीबी संबंध रखने वाले टेलीग्राम चैनल 'बाजा' ने शुरुआत में दावा किया था कि विस्फोट रेस्तरां की रसोई में गैस रिसाव के कारण हुआ, लेकिन बाद में राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी समिति ने इसे बम धमाका बताया।

रिपोर्टों के अनुसार, रेस्तरां में एक निजी जन्मदिन समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें रूसी वायुसेना के कमांडर अलेक्जेंडर चैको भी मौजूद थे।

इससे पहले मॉस्को पुलिस ने रिया नोवोस्ती समाचार एजेंसी को बताया था कि जांचकर्ता और फॉरेंसिक विशेषज्ञ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं। रूसी टेलीग्राम चैनलों पर साझा किये गये।

जिले में डेयरी एनालॉग (नकली पनीर) एवं भ्रामक दुग्ध-जैसे खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध प्रभावी

खाद्य कारोबार संचालकों को नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश, उल्लंघन पर होगी सख्त वैधानिक कार्रवाई

बेमेतरा/मूक पत्रिका

उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा तथा खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में छत्तीसगढ़ शासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य में डेयरी एनालॉग (नकली पनीर) एवं ऐसे गैर-दुग्ध खाद्य उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण एवं विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लागू कर दिया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार यह प्रतिबंध पूरे राज्य सहित जिला बेमेतरा में भी प्रभावशील हो गया है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत जारी इस आदेश का उद्देश्य उपभोक्ताओं को भ्रामक एवं अमानकीकृत खाद्य उत्पादों से संरक्षण प्रदान करना तथा जनस्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। शासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसे उत्पाद, जिनमें दूध के स्थान पर वनस्पति वसा, वनस्पति तेल अथवा अन्य गैर-दुग्ध अवयवों का उपयोग किया जाता है और जिन्हें पनीर, क्रीम, मक्खन अथवा अन्य दुग्ध उत्पादों के समान नाम, स्वरूप, पैकेजिंग अथवा प्रदर्शन के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, अब प्रतिबंधित रहेंगे।

प्रतिबंध विशेष रूप से उन खाद्य उत्पादों पर लागू होगा जो वास्तविक दुग्ध उत्पाद नहीं हैं, जिनमें दूध के स्थान पर गैर-दुग्ध अवयवों का उपयोग किया गया है अथवा जिनकी लेबलिंग, पैकेजिंग, प्रस्तुति या विक्रय की पद्धति उपभोक्ताओं को भ्रमित करने वाली है। ऐसे उत्पादों का निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण एवं विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

जिला बेमेतरा के समस्त खाद्य कारोबार संचालकों, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा संचालकों, मिठाई प्रतिष्ठानों, डेयरी प्रतिष्ठानों, थोक एवं फुटकर विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वे प्रतिबंधित डेयरी एनालॉग अथवा भ्रामक दुग्ध-जैसे खाद्य उत्पादों का किसी भी रूप में निर्माण, भंडारण अथवा विक्रय न करें। सभी प्रतिष्ठानों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम तथा संबंधित नियमों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा बेमेतरा जिले में विशेष निरीक्षण एवं प्रवर्तन अभियान संचालित किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान प्रतिबंधित उत्पादों का निर्माण, भंडारण, परिवहन अथवा विक्रय करते पाए जाने पर संबंधित खाद्य कारोबार संचालकों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर एवं जिला खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने जिले के नागरिकों से भी सहयोग की अपील की है। यदि किसी प्रतिष्ठान में नकली अथवा भ्रामक डेयरी उत्पादों का निर्माण या विक्रय किया जा रहा हो, तो इसकी सूचना तत्काल खाद्य सुरक्षा विभाग को दें, ताकि आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

उपभोक्ताओं से अनुरोध किया गया है कि खाद्य पदार्थ खरीदते समय उत्पाद का लेबल, सामग्री (इंग्रेडिट्स), निर्माण संबंधी जानकारी एवं उत्पाद के वास्तविक स्वरूप की सावधानीपूर्वक जांच करें तथा केवल मानक, प्रमाणित एवं विधिसम्मत खाद्य उत्पादों का ही उपयोग करें। जागरूक उपभोक्ता ही सुरक्षित खाद्य व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं।

सफलता की कहानी: पीएम आशा योजना से किसान को मिला उपज का उचित मूल्य, बढ़ी आय और आत्मविश्वास

बेमेतरा/मूक पत्रिका

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम आशा योजना) किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने में प्रभावी साबित हो रही है। योजना के माध्यम से किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर उपज बेचने का अवसर मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है तथा खेती के प्रति उनका विश्वास लगातार बढ़ रहा है। जिला बेमेतरा के विकासखंड बेमेतरा अंतर्गत ग्राम पचभैया निवासी किसान धनेश चंद्राकर पिछले 16 वर्षों से खेती कर रहे हैं। लगभग 2.67 हेक्टेयर कृषि भूमि पर खेती करने वाले किसान धनेश चंद्राकर ने वर्ष 2025-26 में आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर चना एवं मसूर की बेहतर फसल का उत्पादन किया। उन्होंने अपनी उपज का विक्रय प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम आशा योजना) के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया, जिससे उन्हें उनकी मेहनत का उचित मूल्य प्राप्त हुआ।किसान धनेश चंद्राकर बताते हैं कि पहले उन्हें अपनी उपज कम कीमत पर व्यापारियों को बेचनी पड़ती थी, जिससे अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता था। लेकिन पीएम आशा योजना के माध्यम से उन्हें समर्थन मूल्य पर उपज बेचने का अवसर मिला, जिससे समय पर भुगतान प्राप्त हुआ और उनकी आय में वृद्धि हुई। इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई तथा खेती के प्रति उनका उत्साह भी बढ़ा है। उन्होंने बताया कि योजना से प्राप्त अतिरिक्त आय का उपयोग वे आगामी फसल के लिए बेहतर गुणवत्ता के बीज, उर्वरक एवं आधुनिक कृषि उपकरणों की व्यवस्था करने में कर रहे हैं। साथ ही परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति भी पहले की अपेक्षा अधिक सहजता से हो रही है।

किसान धनेश चंद्राकर ने अन्य किसानों से भी अपील की है कि वे शासन की उपार्जन व्यवस्था का लाभ लेने के लिए अपनी उपज का पंजीयन कराएं तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल बेचकर अपनी मेहनत का उचित लाभ प्राप्त करें। उन्होंने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान को किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी बताते हुए कहा कि इस योजना ने उन्हें आर्थिक सुरक्षा, समय पर भुगतान और आत्मविश्वास प्रदान किया है, जिससे वे भविष्य में और अधिक उत्साह के साथ खेती करने के लिए प्रेरित हुए हैं।

छेवारीपाली जलाशय नहर निर्माण एवं जीर्णोद्धार के लिए वित्त मंत्री चौधरी ने दिए 4 करोड़ से अधिक, दादरपाली, साल्हेओना और धोबनीपाली के किसानों को मिलेगा सीधा लाभ..

सारंगढ़ बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत छेवारीपाली जलाशय के जीर्णोद्धार एवं नहर को पक्की कंक्रीट बनाने हेतु शासन द्वारा 4 करोड़ 29 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। रायगढ़ के विधायक एवं प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा किसानों के हित में लगातार किए जा रहे विकास कार्यों की कड़ी में इस बड़ी सौगात से क्षेत्रवासियों में हर्ष की लहर है।इस दूरगामी और जनहितैषी निर्णय से क्षेत्र के दादरपाली, साल्हेओना एवं धोबनीपाली के हजारों किसानों को सीधा लाभ पहुँचेगा। नहर के पक्की कंक्रीट बनने से खेतों तक पानी की निर्बाध एवं सुचारू आपूर्ति संभव हो सकेगी, जिससे कृषि उत्पादन में सुधार होगा।

बजट में शामिल कराकर दिलाई स्वीकृति-किसान हित में इस महत्वपूर्ण माँग को किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष राधामोहन पाणिग्राही एवं साल्हेओना सोसायटी के प्राधिकृत अधिकारी जयरतन पटेल ने मजबूती से वित्त मंत्री के समक्ष रखा था। जनभावनाओं और किसानों की जरूरत को प्राथमिकता देते हुए मंत्री जी ने इसे बजट में शामिल करवाकर वित्तीय मंजूरी दिलाई। रायगढ़ क्षेत्र के विधायक ओपी चौधरी के इस जनकल्याणकारी कदम के लिए क्षेत्र के किसानों एवं स्थानीय भाजपा नेताओं ने उनका कोटि-कोटि धन्यवाद एवं हार्दिक आभार व्यक्त किया है।

गारे पेलमा कोयला खदान पर सुप्रीम कोर्ट : महाजेनको की नए सिरे से होगी जनसुनवाई! लेकिन खदान का काम नहीं रुकेगा

बंद कमरों में पर्यावरण मंजूरी देने का 'शॉर्टकट' सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज!

जानिए क्या अब खदान का काम रुक जाएगा या गांव वालों को मिलेगी नई ताकत?

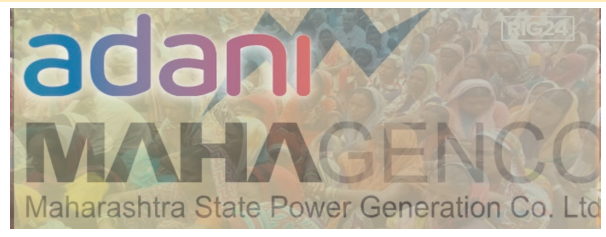

रायगढ़/मूक पत्रिका

जिले की गारे पेलमा सेक्टर-2 कोयला खदान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि बिना जनता की राय जाने, बंद कमरों में पर्यावरण मंजूरी देने का शॉर्टकट अब नहीं चलेगा। इस प्रोजेक्ट के लिए अब गांव वालों के बीच जाकर नए सिरे से जनसुनवाई करनी ही होगी। हालांकि, इस सख्त आदेश के बीच खदान मालिक 'महाजेनको' और इसे चलाने वाले 'अदानी ग्रुप' को एक बड़ी राहत भी मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने खदान में चल रहे मौजूदा माइनिंग के काम पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। अदालत का कहना है कि जब तक नई जनसुनवाई की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, खदान से कोयला निकालने का काम पहले की तरह बदस्तूर जारी रहेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने 24 जुलाई को यह निर्णय दिया, जिसे बाद में अपलोड किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (हृत्रञ्ज) के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें बिना नई जन सुनवाई के दी गई पर्यावरण मंजूरी को स्वीकार कर लिया गया था। शीर्ष अदालत ने इस मामले को वापस हृत्रञ्ज को भेजते हुए निर्देश दिया है कि वह 3 अगस्त से मामले की सुनवाई करे और जन सुनवाई प्रक्रिया की निगरानी करते हुए इसका शीघ्र अंतिम निपटारा करे।'नए सिरे से' प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्यः सुप्रीम कोर्टमामले पर टिप्पणी करते हुए पीठ ने कहा कि हृत्रञ्ज के पिछले आदेश में प्रयुक्त 'नए सिरे से' शब्द का सीधा और स्पष्ट अर्थ यही था कि प्राधिकारियों के लिए नई जन सुनवाई आयोजित करना बाध्यकारी था। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, पुरानी वीडियोग्राफी या दस्तावेजों की समीक्षा करना नई जन सुनवाई का विकल्प नहीं हो सकता।

आम आदमी की भाषा में समझें तो, पर्यावरण मंत्रालय की कमेटी ने बिना गांव वालों को बैठाए, पुराने कागजों और वीडियो के आधार पर ही खदान को हरी झंडी दे दी थी। हृत्रञ्ज ने भी इसे सही मान लिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके को गलत ठहराते हुए कहा कि पुरानी फाइलों को पलटना, जनता के बीच होने वाली नई जनसुनवाई का विकल्प बिल्कुल नहीं हो सकता। अब यह पूरा मामला वापस उसी हृत्रञ्ज के पास पहुंच गया है। कल यानी 3 अगस्त से ट्रिब्यूनल में इस मामले की दोबारा सुनवाई शुरू हो रही है। हृत्रञ्ज को ही अब गांव में होने वाली इस नई जनसुनवाई की पूरी निगरानी करनी है। कुल मिलाकर, सुप्रीम कोर्ट ने आम जनता को अपनी बात रखने का एक और बड़ा मौका दिया है, लेकिन कंपनियों का काम भी बाधित नहीं किया है।

सल्हेओना हाई स्कूल में 'MY BHARAT' अभियान की जानकारी, विद्यार्थियों को राष्ट्र निर्माण से जुड़ने का दिया संदेश..

सारंगढ़-बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

सल्हेओना हाई स्कूल में शुक्रवार को 'MY BHARAT - मेरा युवा भारत' अभियान के तहत विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान छात्रों को केंद्र सरकार की इस पहल की जानकारी देते हुए राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के युवाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से 'MY BHARAT' अभियान चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से युवाओं को कौशल विकास, रोजगार, स्वयंसेवा और विभिन्न सरकारी अवसरों की जानकारी एक ही मंच पर उपलब्ध कराई जाती है।

दो मिनट में पंजीयन की दी जानकारी

कार्यक्रम के दौरान छात्रों को मोबाइल के माध्यम से ओटीपी डालकर केवल दो मिनट में रूङ्ख क्षान्नञ्ज पोर्टल से जुड़ने की प्रक्रिया भी बताई गई। विद्यार्थियों को समझाया गया कि इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद उन्हें स्किल ट्रेनिंग, रोजगार, स्वयंसेवी गतिविधियों और अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी समय-समय पर मिलती रहेगी।

विकसित भारत के संकल्प में युवाओं की भूमिका पर जोर

कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को पूरा करने में युवाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी। विद्यार्थियों से अपील की गई कि वे ऐसे अभियानों से जुड़कर अपनी प्रतिभा का बेहतर उपयोग करें और देश के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाएं। इस अवसर पर सरिया मंडल मंत्री अजय पटेल, रोशन पटेल, सल्हेओना हाई स्कूल के प्राचार्य धरमपाल पटेल सहित विद्यालय के शिक्षकगण और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

कोतरी में अवैध महुआ शराब पर पुलिस की कार्रवाई, 17 लीटर शराब के साथ एक आरोपी गिरफ्तार..

सारंगढ़-बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

जिले में अवैध शराब के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए सारंगढ़ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने ग्राम कोतरी में छापेमारी कर अवैध कच्ची महुआ शराब बेचने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 17 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई

पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा के निर्देश तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निमिषा पाण्डेय के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी प्रमोद यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 1 अगस्त को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ग्राम कोतरी में छापेमारी की। सूचना थी कि एक व्यक्ति अपने घर में बिक्री के लिए बड़ी मात्रा में कच्ची महुआ शराब रखे हुए है। पुलिस ने बताए गए स्थान पर दबिश देकर आरोपी सूरज केंवट (पिता स्व. गजानंद केंवट), निवासी ग्राम कोतरी, थाना सारंगढ़ को पकड़ा। तलाशी के दौरान प्लास्टिक की बोतलों और सिल्वर बर्तन में रखी 17 लीटर कच्ची महुआ शराब, जिसकी अनुमानित कीमत 3,400 रुपये है, बरामद की गई। पुलिस ने शराब को जब्त कर आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज किया।विधिवत गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि जिले में अवैध शराब के निर्माण, परिवहन और बिक्री के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी प्रमोद यादव, सहायक उपनिरीक्षक नरेंद्र मनहर, पीएसआई चंचल, आरक्षक पुरुषोत्तम राठौर, विमल जांगड़े, महिला आरक्षक शकुंतला साहू तथा थाना सिटी कोतवाली के अन्य पुलिसकर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

नशे की कुरीतियों से दूर रहकर समाज और राष्ट्र निर्माण में योगदान दें... कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं

नशा सामाजिक बुराई, युवा नशे से दूर रहकर विकसित भारत का सपना करें साकार: मंत्री दयाल दास बघेल

बेमेतरा/मूक पत्रिका

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री दयाल दास बघेल ने कहा कि नशा एक सामाजिक बुराई है। युवा नशापान से दूर रहकर ही विकसित भारत के सपने को सार्थक बना सकते हैं। मंत्री बघेल ने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि युवा देश की रीढ़ है, युवा देश का भविष्य है। युवा शक्ति से भारत विश्व में परचम लहरा सकता है। युवा शक्ति में जो ताकत है, वह देश को नई ऊंचाइयों और नए मुकाम तक पहुंचाने की ताकत रखती है।उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य को संवारने लगातार काम कर रही है। लेकिन नशे की लत इस पूरी मेहनत पर पानी फेर देती है। इसलिए हर युवा को नशे से दूर रहकर देश और समाज के निर्माण में अपनी ऊर्जा लगानी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज और राष्ट्र के विकास में नशापान सबसे बड़ा बाधक होता। उन्होंने उन्नत,सभ्य, समृद्ध व विकसित देश और समाज के निर्माण में योगदान देने आव्हान किया। मंत्री बघेल ने उक्त विचार आज टाउन हॉल में आयोजित नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा।

युवा राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति... विधायक दीपेश साहू

इस अवसर पर विधायक दीपेश साहू ने कहा कि युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी पूंजी और सबसे बड़ी उम्मीद होते हैं। आज भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने युवाओं को नशे जैसी सामाजिक बुराई से बचाएँ। उन्होंने कहा कि नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित करता है। यह युवाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, खेल, करियर और भविष्य को कमजोर कर देता है। कई प्रतिभाशाली युवा केवल गलत संगति और नशे की लत के कारण अपने जीवन के लक्ष्य से भटक जाते हैं।

उन्होंने कहा कि युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आपका जीवन अनमोल है। अपने सपनों को किसी भी प्रकार के नशे की भेंट मत चढ़ाइए। अपने समय का उपयोग कर अपने गांव, मोहल्ले, विद्यालय, महाविद्यालय और पूरे जिले में नशा मुक्ति का वातावरण तैयार करना होगा। उन्होंने इस अवसर पर आगे कहा कि हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि नशा नहीं, शिक्षा , रोजगार , खेल और स्वस्थ जीवन चुनेंगे। उन्होंने कहा कि एक जागरूक, स्वस्थ और आत्मनिर्भर युवा ही विकसित भारत की मजबूत नींव है। उन्होंने जिले के प्रत्येक युवा से आग्रह किया कि वे स्वयं भी नशे से दूर रहे और कम से कम दस अन्य लोगों को भी नशा मुक्ति के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि यही हमारे उज्ज्वल भविष्य, सशक्त समाज और विकसित भारत की वास्तविक आधारशिला होगी।

नये भारत का भविष्य युवा शक्ति पर निर्भर.... प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं को नशापान से दूर रहने प्रेरित किया । उन्होंने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को सार्थक बनाने के लिए नशामुक्त युवाओं की आवश्यकता है। यह अभियान भारत के नए भविष्य को संवारने में मदद करेगा। उन्होंने आगे कहा कि आज से देशभर में नशामुक्त अभियान शुभारंभ हो रहा है। इस अभियान में देश के युवाओं को सामूहिक भागेदारी के साथ अमूल्य योगदान देने आव्हान किया।

कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई ने कहा कि नशापान की कुरीतियों से समाज को दूर ले जाकर ही हम समाज और राष्ट्र निर्माण में सार्थक योगदान दे सकते हैं। सुश्री ममगाई ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो युवा नशे की राह पर निकल पड़े हैं, उन्हें जागरूक कर नशापान से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जाए। इसके लिए जिले भर में व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जाए।कार्यक्रम में मंत्री दयाल दास बघेल ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों ,युवाओं को नशा मुक्ति का संकल्प दिलाया।इस अवसर पर जिले के प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। समाज कल्याण विभाग द्वारा 3 दिव्यांगों को बैटरीचलित ट्रायसिकल प्रदाय किया गया। स्कूली विद्यार्थियों द्वारा नशामुक्ति पर आधारित नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ रजककार बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद रजक, तेलघानी विकास बोर्ड के अध्यक्ष जितेंद्र साहू,नगर पंचायत बेमेतरा के अध्यक्ष विजय सिंहा, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि अजय साहू सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में स्कूल, कालेज के छात्र छात्राएं, विभागीय अधिकारीगण उपस्थित थे।

रामनामी जनों की उपस्थिति में नेशनल अवार्ड विजेता रामनामी डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रदर्शन

कलेक्टर ने रामनामी समुदाय के वरिष्ठजनों का किया सम्मान

सारंगढ़-बिलाईगढ/मूक पत्रिका

जिले की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और अनूठी पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करने वाली राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित रामनामी समुदाय पर आधारित डॉक्यूमेंट्री का विशेष प्रदर्शन सरसीवा थिएटर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू, पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय भूषण पांडेय, पूर्व विधायक कामदा जोल्हे, गणमान्य नागरिक ज्योति लाल पटेल, जिला एवं ब्लॉक स्तर के विभिन्न विभागों के अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में रामनामी समुदाय के लोगों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया।डॉक्यूमेंट्री में रामनामी समुदाय के इतिहास, इसकी स्थापना, समाज की अनूठी परंपराओं, धार्मिक आस्था, जीवन शैली तथा सांस्कृतिक विरासत को बेहद प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। इसमें यह भी दिखाया गया कि रामनामी

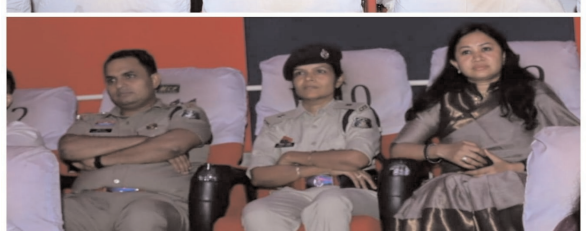

समुदाय का उद्भव कैसे हुआ, समाज के लोग अपने शरीर पर भगवान श्रीराम का नाम अंकित कर किस प्रकार अपनी आस्था का प्रदर्शन करते हैं तथा रामनामी मेले का आयोजन किस तरह होता है। मेले में होने वाले धार्मिक अनुष्ठान, भजन-कीर्तन, सामूहिक रामायण पाठ और सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों को भी डॉक्यूमेंट्री में सुंदर ढंग से चित्रित किया गया है। डॉक्यूमेंट्री के प्रदर्शन के बाद कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू एवं उपस्थित अधिकारियों ने रामनामी समुदाय के वरिष्ठजनों का श्रीफल, शॉल तथा रामायण ग्रंथ भेंट कर सम्मान किया। इस दौरान रामनामी समाज के लोगों ने भी जिला प्रशासन के इस सम्मान और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के प्रयासों की सराहना की। कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू ने कहा कि रामनामी समुदाय केवल सारंगढ़-बिलाईगढ़ ही नहीं, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान है। इस समाज की परंपराएं, आस्था और जीवन मूल्य आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। 72वे राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त यह डॉक्यूमेंट्री सारंगढ़ बिलाईगढ़, सक्ति और जांजगीर चाम्पा जिले के लिए गर्व का विषय है और इससे देश-दुनिया के लोग रामनामी समाज की समृद्ध विरासत से परिचित होंगे। कार्यक्रम में बिलाईगढ़ एसडीएम प्रफुल्ल रजक, सरसीवा तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर, पटवारी, विभिन्न विभागों के जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, जनप्रतिनिधिगण तथा बड़ी संख्या में रामनामी समुदाय के सदस्य उपस्थित रहे। पूरे आयोजन का वातावरण श्रद्धा, सम्मान और सांस्कृतिक गौरव से ओतप्रोत रहा। यह आयोजन जिले की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित एवं प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित इस डॉक्यूमेंट्री ने न केवल रामनामी समुदाय की ऐतिहासिक विरासत को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया, बल्कि जिले की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान भी दिलाई।

झोले में गांजा रखकर ग्राहकों की तलाश में 1.575 किग्रा गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार

कांकेर/मूक पत्रिका

विक्रम ठाकुर/:- उत्तर बस्तर कांकेर पुलिस द्वारा जिले में अवैध नशे के कारोबार पर नकेल कसने के लिए चलाए जा रहे ÷उजियारा अभियान÷ के तहत भानुप्रतापपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गांजा बेचने की फिराक में घूम रहे एक आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 1.575 किलोग्राम अवैध गांजा और बिक्री की नगद राशि बरामद की गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस अधीक्षक निखिल अशोक कुमार राखेचा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश श्रीश्रीमाल के मार्गदर्शन एवं अनुविभागीय अधिकारी (एसडीओपी) शेर बहादुर सिंह ठाकुर के पर्यवेक्षण में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में थाना प्रभारी भानुप्रतापपुर निरीक्षक अंबर सिंह

भारद्वाज को मुखबिर से सूचना मिली कि संबलपुर कराठी रोड स्थित अटल आवास के मुख्य मार्ग के पास एक व्यक्ति झोले में गांजा रखकर ग्राहकों की तलाश कर रहा है। पुलिस टीम का गठन कर बताए गए स्थान पर घेराबंदी की गई। पुलिस ने मौके से संदेही को पकड़ा, जिसने पूछताछ में अपना नाम किशोर जैन (35 वर्ष), निवासी संबलपुर (बस स्टैंड के पास), थाना भानुप्रतापपुर बताया। तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से 1.575 किलोग्राम गांजा (कीमत लगभग ?79,000) तथा गांजा बिक्री के ?2,600 नगद बरामद किए गए। पुलिस ने कुल ?81,600 मूल्य का माल जब्त किया है। भानुप्रतापपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 155/2026 धारा 20 (बी) एनडीपीएस एक्ट (ह्ष्ठक्क्र/ष्ह्ल) के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा (जेल) में भेज दिया गया है। कार्रवाई में शामिल पुलिस निरीक्षक अंबर सिंह भारद्वाज, उप निरीक्षक प्रेम कुमार झा, प्रधान आरक्षक ,विजय कटकवार, आरक्षक , टोमन साहू, आरक्षक, गौतम हुपेंडी एवं महिला सहायक आरक्षक मीनाक्षी मरकाम की सराहनीय भूमिका रही।

शिलान्यास पहले, निर्माण अधूराः दो महीने में ही क्षतिग्रस्त हुई नाली, गुणवत्ता पर उठे सवाल

खरसिया/मूक पत्रिका

नगर पालिका खरसिया द्वारा वार्ड क्रमांक 11 में बेनी पेट्रोल पंप से अंबेडकर चौक तक सीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्य कराया जा रहा है। निर्माण कार्य की अनुमानित लागत 3.79 लाख रुपये बताई गई है। हालांकि, स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि निर्माण कार्य अभी पूरी तरह पूरा भी नहीं हुआ है, लेकिन उसका शिलान्यास कर दिया गया। शिलान्यास पट्टिका पर न तो कार्य प्रारंभ होने की तिथि अंकित है और न ही कार्य पूर्ण होने की जानकारी दी गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार निर्माण कार्य शुरू हुए करीब दो महीने ही हुए हैं, लेकिन इस दौरान ही नाली कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त दिखाई देने लगी है। नागरिकों

का कहना है कि निर्माण की गुणवत्ता बेहद खराब है और नाली का निर्माण अंबेडकर चौक तक ही सीमित रह गया है। आगे के हिस्से में नाली अधूरी होने के कारण बारिश का पानी सड़क पर जमा हो रहा है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता की अनदेखी कर सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया है। उनका कहना है कि यदि मौके पर निरीक्षण किया जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि नाली का निर्माण अधूरा है और कई स्थानों पर पानी का उचित निकास नहीं होने से जलभराव की स्थिति बनी रहती है। नागरिकों ने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, निर्माण कार्य की गुणवत्ता की तकनीकी जांच हो तथा यदि अनियमितता या भ्रष्टाचार की पुष्टि होती है तो संबंधित ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अब देखना होगा कि नगर प्रशासन इस मामले में प्रभावी कदम उठाता है या फिर मामला केवल कागजी कार्रवाई तक ही सीमित रह जाता है।

सचिव बोले- फर्म संचालित है, शिकायतकर्ता ने बताया .. 15 वें वित्त आयोग भुगतानों की जांच तेज

शिकायत कर्ता ने लगाया टैक्स इनवॉइस में तिथि व जीएसटी विवरण नहीं होने का आरोप, फर्म के अस्तित्व पर सवाल; प्रशासनिक जांच के दायरे में पूरा मामला

धरमजयगढ़/मूक पत्रिका

जनपद पंचायत धरमजयगढ़ की ग्राम पंचायत पारेमेर में 15वें वित्त आयोग की राशि से किए गए भुगतानों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। लोक शिकायत निवारण पोर्टल के माध्यम से की गई शिकायत के बाद मामला कलेक्टर कार्यालय रायगढ़ पहुंच चुका है, जहां संबंधित अभिलेखों की प्रशासनिक जांच प्रारंभ कर दी गई है। शिकायत में पंचायत द्वारा किए गए भुगतानों की पारदर्शिता, लेखा प्रक्रिया और वित्तीय नियमों के पालन पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं।शिकायतकर्ता का आरोप है कि पंचायत ने 'निधि ट्रेडर्स' नामक जीएसटी पंजीकृत फर्म को लाखों रुपये का भुगतान किया, जबकि फर्म के पंजीकृत पते के

भौतिक सत्यापन के दौरान वहां न दुकान मिली, न गोदाम और न ही किसी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि संचालित होती दिखाई दी। शिकायतकर्ता का दावा है कि आसपास के ग्रामीणों और व्यापारियों से पूछताछ में भी ऐसी किसी सक्रिय फर्म की जानकारी सामने नहीं आई। शिकायत में प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार, बिल क्रमांक 72 में क्रेशर गिट्टी के लिए ?50,000 तथा मिक्सर मशीन किराये के लिए ?21,700 सहित कुल ?71,700 का भुगतान दर्शाया गया है। बिल पर "TAX INVOICE" अंकित होने के बावजूद उसमें ष्टत्रस्ञ्ज और स्त्रस्ञ्ज का विवरण रिक्त बताया गया है। साथ ही, बिल पर तिथि अंकित नहीं होने का भी आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि ऐसे टैक्स इनवॉइस की वैधता और कर नियमों के अनुपालन की तकनीकी जांच आवश्यक है। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। मामले में पंचायत सचिव ने फोन पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान संबंधित फर्म के संचालित होने का दावा किया और कहा कि फर्म अस्तित्व में है। दूसरी ओर शिकायतकर्ता का कहना है कि पंजीकृत पते पर किसी प्रकार का व्यवसायिक प्रतिष्ठान नहीं मिला। इसी विरोधाभास ने पूरे मामले को और अधिक चर्चा में ला दिया है। फिलहाल दोनों पक्षों के दावों की सत्यता प्रशासनिक जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि संबंधित वेंडर के बिल केवल ग्राम पंचायत पारेमेर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अन्य पंचायतों में भी भुगतान के लिए उपयोग किए गए हैं। शिकायतकर्ता ने पूरे प्रकरण में संभावित मिलीभगत की निष्पक्ष जांच और सभी संबंधित भुगतानों की समीक्षा की मांग की है। शिकायतकर्ता ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (ष्टक्चढ्ढष्ट), राज्य कर विभाग और जिला प्रशासन से फर्म के पंजीकृत पते का भौतिक सत्यापन, जीएसटी दस्तावेजों की तकनीकी जांच तथा ग्राम पंचायत पारेमेर द्वारा 15वें वित्त आयोग मद से किए गए सभी भुगतानों का स्वतंत्र वित्तीय ऑडिट कराने की मांग की है। साथ ही, यदि जांच में अनियमितता सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों और वेंडर के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की मांग भी की गई है।फिलहाल पूरा मामला प्रशासनिक जांच के अधीन है। शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि या खंडन जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगा। जांच के निष्कर्ष और सक्षम प्राधिकारी की कार्रवाई पर अब सभी की नजरें टिकी हैं।

रायगढ़ समेत तीन जिलों में ही मिली अफीम की खेती

रायगढ़/मूक पत्रिका

अफीम की खेती को लेकर अचानक से प्रदेश की सियासत गर्म हो गई थी जब दुर्ग में एक भाजपा नेता के खेत में अफीम की खेती पाई गई। इसके बाद दूसरे जिलों में भी पड़ताल हुई, लेकिन तीन ही जिलों में से जानकारी सामने आई। रायगढ़ समेत तीन जिलों में अफीम के खेत पाए गए। रायगढ़ में करीब 3 हजार किलो अफीम जब्त की गई। राजस्व विभाग और पुलिस की नाक के नीचे लोगों ने खेतों में अफीम की फसल उगाई। बेखौफ तरीके से कई एकड़ में अफीम लगाकर इसे बेचने का भी सिस्टम तैयार किया। एक जिले में खुलासा हुआ तो फिर दूसरे जिलों में भी इसकी पड़ताल की जाने लगी।सबसे पहले दुर्ग में अफीम की खेती पकड़ी गई। वहां एक ही प्रकरण में आठ आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। कुल 62424 किलो अफीम भी जब्त की गई थी। इसके बाद रायगढ़ जिले में चार जगहों पर अफीम की खेती पाई गई।

चार प्रकरणों में 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसकी जानकारी अब जाकर सामने आई है। जिले में इन चार प्रकरणों में 2963 किलो अफीम जब्त की गई है। सभी मामले लैलूंगा, धरमजयगढ़ क्षेत्र के हैं। विधानसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक चारों मामलों में कार्यवाही पुलिस स्तर पर पेंडिंग है। इसके अलावा बलरामपुर में दो प्रकरणों में 6228 किलो अफीम जब्त की गई जिसमें 13 आरोपी गिरफ्तार किए गए।सप्लाई चेन का नहीं पता चला रायगढ़ जिले में चार जगहों पर अफीम की खेती पकड़े जाने के बाद हडक़ंप मच गया। खेती करने वाले और भूमि स्वामी पर तो कार्रवाई हुई। लेकिन इस बात का पता नहीं चला कि इसकी सप्लाई कहां की जाती थी। किसके माध्यम से अफीम को बाजार में खपाया जाता था।

11वें जन्मदिन पर एशल ने पेश की मिसाल, गुल्लक की बचत बाढ़ पीड़ितों के नाम

- मुख्यमंत्री राहत कोष में राशि समर्पित कर सेवा और सामाजिक सरोकार का दिया संदेश

गीदम/दंतेवाडा/मूक पत्रिका

अपने 11वें जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए गीदम की एशल अंसारी ने ऐसा कदम उठाया, जिसकी हर ओर सराहना हो रही है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की जिला अध्यक्ष नरगिस अंसारी की पुत्री एशल ने अपनी गुल्लक में वर्षों से संचित बचत राशि मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम से असम के बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए समर्पित कर सेवा और मानवता का संदेश दिया।मिली जानकारी अनुसार एशल ने जन्मदिन पर उपहार और उत्सव की बजाय जरूरतमंद लोगों की मदद को प्राथमिकता दी। उनकी इस पहल

को सामाजिक, राजनीतिक और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने प्रेरणादायी बताते हुए कहा कि ऐसे संस्कार समाज में संवेदनशील और जिम्मेदार पीढ़ी तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।नरगिस अंसारी ने कहा कि बच्चों में बचपन से ही सेवा, सहयोग और राष्ट्रहित की भावना विकसित करना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि एशल का यह निर्णय परिवार से मिले संस्कारों का परिणाम है। उनका कहना था कि छोटी-छोटी बचत भी आपदा की घड़ी में पीड़ित परिवारों के लिए बड़ी राहत बन सकती है। एशल अंसारी की इस पहल को लोगों ने सामाजिक उत्तरदायित्व का अनुकरणीय उदाहरण बताया। उनका मानना है कि यदि बच्चे अपने विशेष अवसरों को जनसेवा से जोड़ें तो समाज में सकारात्मक सोच और सहयोग की भावना को और मजबूती मिलेगी।

साप्ताहिक बाजार में पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान, हेलमेट, सीट बेल्ट और ट्रैफिक नियमों के पालन की अपील

बीजापुर/मूक पत्रिका

साप्ताहिक बाजार में रविवार को बीजापुर पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान सबसे अधिक जोर इस बात पर दिया गया कि अभिभावक अपने नाबालिग बच्चों को किसी भी स्थिति में वाहन चलाने के लिए न दें। पुलिस ने चेताया कि यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहन मालिक और अभिभावक के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।अभियान के दौरान यातायात पुलिस ने बाजार में मौजूद पालकों, वाहन चालकों, युवाओं और आम लोगों से सीधे संवाद किया। पुलिस ने बताया कि बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस और पर्याप्त अनुभव के वाहन चलाना सड़क हादसों का प्रमुख कारण है। इसलिए बच्चों की

सुरक्षा और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए अभिभावकों की जिम्मेदारी सबसे महत्वपूर्ण है। पुलिस ने लोगों को हेलमेट पहनकर दोपहिया चलाने, कार में सीट बेल्ट लगाने, निर्धारित गति सीमा का पालन करने, शराब पीकर वाहन नहीं चलाने और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करने की समझाइश दी। साथ ही सभी से यातायात संकेतों का पालन कर सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। यातायात पुलिस का कहना है कि सड़क सुरक्षा केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की भागीदारी से ही दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है।

डी ए वी जांता बालक-बालिकाओं का क्लस्टर लेवल खेलों में रहा दबदबा

डी.ए.वी. मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल, जांता के खिलाड़ियों का क्लस्टर स्पोर्ट्स में शानदार प्रदर्शन, चार वर्गों में कबड्डी चैंपियन बनने का गौरव

बेमेतरा/मूक पत्रिका

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ खेल, अनुशासन एवं व्यक्तित्व विकास को समान महत्व देने वाले डी.ए.वी. मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल, जांता के विद्यार्थियों ने डी.ए.वी. क्लस्टर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए विद्यालय एवं जिले का नाम गौरवान्वित किया। प्रतियोगिता का आयोजन कबड्डी (नंदिनी), खो-खो (जामुल) एवं एथलेटिक्स (सेक्टर-2, भिलाई) अन्य खेल डी ए वी हुडको भिलाई में संपन्न हुआ, जहाँ विद्यालय के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा, अनुशासन एवं टीम भावना का उत्कृष्ट परिचय दिया। एथलेटिक्स प्रतियोगिता में अंडर-17 वर्ग के सीताराम ने 1500 मीटर दौड़ एवं 800 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त कर दो स्वर्ण पदक अपने नाम किए। एवं अंडर-14 वर्ग के मोहन साहू ने 1500 मीटर दौड़ में प्रथम एवं हाई जम्प में प्रथम स्थान प्राप्त कर इन्होंने ने भी दो स्वर्ण पदक अपने नाम किया, वही आयुष ध्रुवे ने 800मीटर दौड़ में

तृतीय स्थान कांस्य पदक प्राप्त किया। नारायण यादव ने 400 मीटर दौड़ में तृतीय स्थान के साथ कांस्य पदक प्राप्त किया, जबकि धनेश्वर ने लॉन्ग जंप में तृतीय स्थान के साथ कांस्य पदक अर्जित किया। विद्यालय की अंडर 17 रिले रेस 4म400 टीम ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए द्वितीय स्थान प्राप्त किया। कबड्डी प्रतियोगिता में विद्यालय की अंडर-14 बालक, अंडर-14 बालिका, अंडर-17 बालक एवं अंडर-17 बालिका चारो टीमों ने अपने उत्कृष्ट खेल कौशल के बल पर प्रथम स्थान स्वर्ण पदक हासिल करते हुए चारों वर्गों में चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। वहीं अंडर-19 बालक कबड्डी टीम ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। खो-खो प्रतियोगिता में विद्यालय की अंडर-14 बालक एवं अंडर-14 बालिका टीमों ने द्वितीय स्थान अर्जित कर विद्यालय की उपलब्धियों में एक और गौरवपूर्ण अध्याय जोड़ा। विद्यालय के प्राचार्य पी. एल. जायसवाल ने सभी विजेता खिलाड़ियों, खेल प्रशिक्षकों एवं अभिभावकों को बधाई देते हुए कहा कि डी.ए.वी. मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल, जांता विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। विद्यालय में शिक्षा के साथ-साथ खेल, संस्कार, नेतृत्व क्षमता एवं अनुशासन पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिसका परिणाम है कि विद्यालय के विद्यार्थी निरंतर जिला, क्लस्टर एवं उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रचार्य जायसवाल ने आगे जानकारी साझा किया कि विद्यालय के खेल प्रभारी शिक्षक अकलेश पटेल के नेतृत्व में विद्यालय के विद्यार्थियों ने प्रत्येक वर्ष नेशलन स्पोर्ट्स दिल्ली मे शामिल होकर विद्यालय के नाम को ऊंचा कर रहे हैं,विद्यालय परिवार ने सभी खिलाड़ियों, खेल प्रभारी शिक्षक एवं सहयोगी शिक्षकों को इस उल्लेखनीय सफलता के लिए शुभकामनाएँ देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि भविष्य में भी विद्यालय के विद्यार्थी राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय, जिले एवं प्रदेश का नाम रोशन करेंगे।

संपादकीय

राष्ट्रमंडल खेल की घटती प्रासंगिकता

रविवार को ग्लासगो में ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप पदक-विजेता मीराबाई चानू जब पोडियम पर खड़ी हुईं, तो राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार तीसरी बार स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला वेटलिफ्टर बनने के बाद उनके गालों पर आंसू ढुलक पड़े। उनकी इस उपलब्धि ने इन खेलों को, जिनके कुछ साल पहले गुमनामी में चले जाने का खतरा पैदा हो गया था, बड़ा सहारा प्रदान किया। यह देखते हुए कि भारत साल 2030 में अहमदाबाद में इन खेलों के शतवार्षिकी संस्करण की मेजबानी की तैयारी कर रहा है, मीराबाई की स्वर्णिम विजय से बेहतर कोई विज्ञापन नहीं हो सकता था। कुल 190 किलोग्राम के साथ महिलाओं के 48-किलोग्राम वर्ग में यह उनका लगातार चौथा पदक था, अगर पदक के रंग पर न जाएं तो। स्कॉटलैंड के इस शहर में, तपी-तपायी वेटलिफ्टर का कारनामा शायद इकलौता गौरवशाली अध्याय न रहे, क्योंकि एथलेटिक्स व पैरा-एथलेटिक्स, वेटलिफ्टिंग व पैरा-वेटलिफ्टिंग, बॉक्सिंग, जूडो, और लॉन बॉल्स व पैरा-बॉल्स में भी भारत के दूसरे अग्रणी एथलीटों के पोडियम तक पहुंचने की उम्मीद है। केंद्रीय खेल मंत्रालय के एक अंदरूनी अनुमान के मुताबिक, भारतीय एथलीटों के लगभग 30 पदक जीतने की उम्मीद है, भले ही ग्लासगो में छोटे स्तर के इस आयोजन से कई ऐसे खेल हटा दिये गये जिनमें भारतीय पारंपरिक रूप से अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं – जैसे कि कुश्ती, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी और स्क्वॉश। नीरज चोपड़ा, मुरली श्रीशंकर, प्रवीण चिथ्रवेल, और मुक्केबाजों लवलीना बरगोंहाई और जैस्मिन लंबोरिया से पदक की उम्मीद है।

छोटे किये गये राष्ट्रमंडल खेल पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य की इस खेल परंपरा की घटती प्रासंगिकता को उजागर करते हैं। मूल रूप से विक्टोरिया को आवंटित 2026 संस्करण के सामने उस समय अस्तित्व का खतरा पैदा हो गया था जब इस ऑस्ट्रेलियाई राज्य ने बढ़ती लागत के चलते तीन साल पहले मेजबानी से पैर खींच लिये। साल 2014 में मेजबान रहे ग्लासगो ने, आठ मील के गलियारे के भीतर चार आयोजन स्थलों में 10 एकीकृत खेलों वाले, एक संक्षिप्त संस्करण का प्रस्ताव रखकर इन खेलों को शर्मिंदगी से बचाया। भले ही राष्ट्रमंडल खेल ओलंपिक या एशियाई खेलों की वैश्विक या क्षेत्रीय उत्कृष्टता के जोड़ के नहीं हैं, यह मंच अब भी भारतीय खिलाड़ियों और प्रशासकों के लिए काफी आकर्षण रखता है। अलग-अलग खेलों में एलीट विश्व स्तर पर भारत की सफलता छिटपुट रही है, लेकिन उसने लगातार तीन साल तक ग्लोबल डोपिंग चार्ट में शीर्ष पर रहने की अपमानजनक विशिष्टता दिखायी है। ग्लासगो 2026 के आयोजन से पहले भी, अलग-अलग खेलों के कई एथलीट प्रतिबंधित पदार्थों का सेवन करने के लिए पकड़े गए हैं।

बिट्टू की एंट्री से बदली पंजाब की चुनावी बिसात, नया समीकरण गढ़ने में भाजपा कामयाब

(नीरज कुमार दुबे)

दरअसल, रवनीत सिंह बिट्टू की वापसी भाजपा की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है, जिसके तहत पार्टी पंजाब में अपने पारंपरिक शहरी हिंदू वोट बैंक से आगे बढ़कर सिख, दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग के बीच भी मजबूत आधार तैयार करना चाहती है।

केंद्रीय मंत्री पद से रवनीत सिंह बिट्टू का इस्तीफा पंजाब की राजनीति में भाजपा के सबसे बड़े चुनावी दांव के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि बिट्टू विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं और पार्टी के चुनाव अभियान का प्रमुख चेहरा भी बन सकते हैं। उल्लेखनीय है कि रवनीत सिंह बिट्टू का राज्यसभा कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो चुका था। इसके बाद उन्होंने रेल तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया। बिट्टू ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें देश और विशेष रूप से पंजाब की सेवा करने का अवसर मिला तथा उनका सार्वजनिक जीवन राष्ट्रवाद, सेवा और विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे भी जारी रहेगा।

पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पौत्र बिट्टू लंबे समय तक कांग्रेस में रहे। वर्ष 2009 में वह आनंदपुर साहिब से सांसद बने और बाद में दो बार लुधियाना का प्रतिनिधित्व किया। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने भाजपा का दामन थामा, लेकिन लुधियाना से कांग्रेस के अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के खिलाफ चुनाव हार गए। इसके बाद उन्हें राजस्थान से राज्यसभा भेजा गया और केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया।

पंजाब की राजनीति में बिट्टू की वापसी इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि वह पिछले कुछ समय से पंजाब में भाजपा के संगठन और चुनावी तैयारी में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने पहले ही सार्वजनिक रूप से दावा किया था कि भाजपा का लक्ष्य पंजाब में डबल इंजन सरकार बनाना है और प्रधानमंत्री मोदी के विकास के विजन को हर विधानसभा क्षेत्र तक पहुंचाना है।

दरअसल, बिट्टू की वापसी भाजपा की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है, जिसके तहत पार्टी पंजाब में अपने पारंपरिक शहरी हिंदू वोट बैंक से आगे बढ़कर सिख, दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग के बीच भी मजबूत आधार तैयार करना चाहती है। पंजाब में लगभग 58 प्रतिशत आबादी सिखों की है, जबकि करीब 39 प्रतिशत हिंदू हैं। इसके अलावा राज्य में लगभग 32 प्रतिशत दलित और लगभग 16 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग है। भाजपा की कोशिश इन चारों सामाजिक वर्गों में समानांतर स्वीकार्यता बढ़ाने की है।

भाजपा की इसी नई रणनीति की झलक हाल में आई सतलुज फिल्म को लेकर हुए विवाद में भी देखने को मिली थी। रवनीत सिंह बिट्टू ने फिल्म का खुलकर विरोध करते हुए आरोप लगाया कि यह ऐसे संवेदनशील विषय को उभारने का प्रयास है, जिससे पंजाब का माहौल दोबारा तनावपूर्ण हो सकता है। उन्होंने इसे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली कोशिश बताते हुए फिल्म पर सवाल उठाए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिट्टू का यह रुख भाजपा की बदली हुई चुनावी रणनीति का संकेत था। पहले जहां पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दों पर अपेक्षाकृत आक्रामक भाषा का प्रयोग करती थी, वहीं अब वह सिख समुदाय की धार्मिक और ऐतिहासिक संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी राजनीतिक अभिव्यक्ति को अधिक संतुलित और संयमित बना रही है। माना जा रहा है कि भाजपा पंजाब में सिख मतदाताओं के बीच भरोसा बढ़ाने के लिए ऐसे मुद्दों पर सावधानीपूर्वक राजनीतिक संदेश देना चाहती है, ताकि हिंदू, सिख, दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग, इन चारों प्रमुख सामाजिक समूहों में समानांतर स्वीकार्यता विकसित की जा सके।

राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि शिरोमणि

हालांकि शिरोमणि अकाली दल के साथ भाजपा के रिश्तों को लेकर राजनीतिक अटकलें अब भी खत्म नहीं हुई हैं। इसका ताजा उदाहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान देखने को मिला था। जालंधर की सभा में प्रधानमंत्री ने आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अकाली दल तीनों पर निशाना साधते हुए कहा कि अकाली दल भी आपसी स्वार्थों के कारण पंजाब की प्रभावी सेवा नहीं कर पाया। प्रधानमंत्री ने किसी विशेष अकाली गुट का नाम नहीं लिया, लेकिन शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने बाद में दावा किया कि यह टिप्पणी उनकी पार्टी पर नहीं, बल्कि अन्य अकाली धड़ों के लिए थी।

अकाली दल से गठबंधन टूटने के बाद भाजपा ने स्वतंत्र राजनीतिक ताकत बनने की दिशा में लगातार काम किया है। इसका असर चुनावी आंकड़ों में भी दिखा, जहां 2022 विधानसभा चुनाव में लगभग 6.6 प्रतिशत मत पाने वाली भाजपा का वोट प्रतिशत 2024 के लोकसभा चुनाव में बढ़कर लगभग 19 प्रतिशत तक पहुंच गया। यही कारण है कि पार्टी अब पंजाब में अकेले दम पर सत्ता हासिल करने का सपना देख रही है।

हालांकि शिरोमणि अकाली दल के साथ भाजपा के रिश्तों को लेकर राजनीतिक अटकलें अब भी खत्म नहीं हुई हैं। इसका ताजा उदाहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान देखने को मिला था। जालंधर की सभा में प्रधानमंत्री ने आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अकाली दल तीनों पर निशाना साधते हुए कहा कि अकाली दल भी आपसी स्वार्थों के कारण पंजाब की प्रभावी सेवा नहीं कर पाया। प्रधानमंत्री ने किसी विशेष अकाली गुट का नाम नहीं लिया, लेकिन शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने बाद में दावा किया कि यह टिप्पणी उनकी पार्टी पर नहीं, बल्कि अन्य अकाली धड़ों के लिए थी। इस बयान ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी, क्योंकि भाजपा और अकाली दल का लगभग 25 वर्षों पुराना गठबंधन 2020 में कृषि कानूनों के मुद्दे पर टूटने के बाद भी दोनों दलों के हर सार्वजनिक बयान को संभावित राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जाता है। हालांकि भाजपा नेतृत्व फिलहाल गठबंधन पुनर्जीवित करने की किसी संभावना से इंकार कर रहा है और अपने संगठन को स्वतंत्र रूप से मजबूत करने की बात कह रहा है, फिर भी राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पंजाब की राजनीति में भाजपा और अकाली दल के संबंध इतने महत्वपूर्ण रहे हैं कि दोनों दलों के बीच होने वाला हर संवाद भविष्य की संभावनाओं के नजरिए से परखा जाता है। राजनीति

साथ ही भाजपा ने अपने राजनीतिक संदेश और भाषा में भी उल्लेखनीय बदलाव किया है। कभी ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर बेहद आक्रामक रुख अपनाने वाली पार्टी अब सिख समाज की धार्मिक भावनाओं और ऐतिहासिक शिकायतों को अधिक संवेदनशीलता से संबोधित करती दिखाई दे रही है। पार्टी लगातार कांग्रेस को ऑपरेशन ब्लू स्टार, पंजाब में आतंकवाद के दौर और 1984 के सिख विरोधी दंगों के लिए जिम्मेदार ठहराती है, जबकि स्वयं को सिख समाज की भावनाओं का सम्मान करने वाली पार्टी के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही है।

देखा जाये तो भाजपा की इस बदली हुई राजनीतिक रणनीति की पृष्ठभूमि को समझने के लिए उसके पुराने रुख पर भी नजर डालना जरूरी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी आत्मकथा माय कंट्री, माय लाइफ में पंजाब में उग्रवाद के दौर के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने अपने राजनीतिक हितों के लिए उग्रवाद को बढ़ावा दिया और हालात इतने बिगड़ने दिए कि अंततः ऑपरेशन ब्लू स्टार की नौबत आ गई। आडवाणी ने यह भी लिखा था कि भाजपा और अन्य दलों के देशव्यापी आंदोलनों के दबाव में तत्कालीन केंद्र सरकार को स्वर्ण मंदिर परिसर से उग्रवादियों को हटाने के लिए सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी थी। हालांकि अब पंजाब में चुनावी विस्तार की कोशिशों के बीच भाजपा की सार्वजनिक भाषा पहले की तुलना में कहीं अधिक संतुलित और संवेदनशील दिखाई देती है। पार्टी अब ऑपरेशन ब्लू स्टार को राष्ट्रीय त्रासदी बताते हुए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराती है, लेकिन साथ ही सिख समाज की धार्मिक भावनाओं और ऐतिहासिक पीड़ा को भी प्रमुखता से स्वीकार करने का प्रयास कर रही है।

इसी बदलाव के तहत भाजपा ने हाल के वर्षों में कई प्रतीकात्मक और राजनीतिक कदम उठाए हैं। वीर बाल दिवस की घोषणा, करतारपुर साहिब गलियारे का उद्घाटन, अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप भारत लाना, 1984 दंगों के मामलों की जांच में तेजी, हवाई अड्डों पर कृपाण ले जाने की अनुमति, स्वर्ण मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लगातार दौरे तथा लंबे समय से जेल में बंद कुछ सिख कैदियों को मानवीय आधार पर राहत जैसे फैसलों को इसी व्यापक सिख पहुंच अभियान का हिस्सा माना जा रहा है। भाजपा ने यह भी संकेत दिया है कि सत्ता में आने पर धर्मांतरण विरोधी कानून लाया जा सकता है। भौगोलिकसंदर्भ हालांकि भाजपा इस पूरे अभियान के दौरान एक संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रही है। पार्टी स्पष्ट करती है कि उसका आतंकवाद और खालिस्तानी हिंसा के प्रति रुख नहीं बदला है। पंजाब भाजपा के नेताओं का कहना है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार को राष्ट्रीय त्रासदी मानने का अर्थ आतंकवाद का समर्थन नहीं है, बल्कि उस समय की परिस्थितियों के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराना है। फिर भी भाजपा की इस नई राजनीतिक भाषा को लेकर संदेह भी कम नहीं है। कई राजनीतिक विश्लेषकों और सिख बुद्धिजीवियों का मानना है कि पार्टी का यह बदलाव मुख्य रूप से चुनावी गणित से प्रेरित है। उनका कहना है कि केवल हिंदू मतों के सहारे पंजाब में सरकार बनाना संभव नहीं है, इसलिए भाजपा सिख मतदाताओं के बीच स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए अपने राजनीतिक संदेश को नया स्वरूप दे रही है। बहरहाल, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भाजपा की सामाजिक समीकरणों पर आधारित नई रणनीति और सिख समाज तक पहुंच बनाने की कोशिश पंजाब के मतदाताओं को प्रभावित कर पाएगी या फिर राज्य की पारंपरिक राजनीतिक ध्रुवीकरण की राजनीति ही चुनाव परिणाम तय करेगी। अगले विधानसभा चुनाव इस सवाल का सबसे बड़ा जवाब साबित होंगे।(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

संसद में आक्रामकता बनाम रक्षात्मकता- कैसे विपक्ष के दबाव में झुकी सरकार

(सुधीश पचौरी)

सरकार जितना 'हाथजोड़ू मुद्रा' में नजर आती है, उतने ही सबसे बड़े विपक्षी दल के तेवर कड़े होते दिखते हैं। अफसोस कि सत्तापक्ष के पास इसका कोई तोड़ नहीं !सत्तापक्ष, विपक्ष के आगे एक 'हाथजोड़ू प्रार्थना' है। इसके बरक्स विपक्ष एक 'शोर' है, 'नारेबाजी' है, 'काला वस्त्र' है और 'पोस्टर' है। एक जिद है कि हमारा एजंडा मानो, तब चलने देंगे संसद यानी हम चलाएंगे संसद..। सत्तापक्ष आग्रह करता है ⊃ हे विपक्ष जी! कृपया संसद चलने दें, सरकार हर मुद्दे पर विचार करने के लिए तैयार है, नियम एवं समय तय करने पर विचार करेंगे। आसन की ओर से भी विपक्ष के नेताओं से बार-बार आग्रह किया जाता है कि आप वरिष्ठ अनुभवी सांसद हैं, शोर न करें, पोस्टर न लहराएं, सदन चलने दें..। कुछ देर बाद संसद पहले बारह बजे तक, फिर दो बजे, फिर तीन बजे तक और चार बजे तक स्थगित होती रहती है।. सरकार जितना 'हाथजोड़ू मुद्रा' में नजर आती है, उतने ही सबसे बड़े विपक्षी दल के तेवर कड़े होते दिखते हैं। अफसोस कि सत्तापक्ष के पास इसका कोई तोड़ नहीं! जब से मानसून सत्र शुरू हुआ है, तभी से विपक्ष आक्रामक है और सत्तापक्ष रक्षात्मक! विपक्ष पूरी तरह सक्रिय है और उसमें राहुल गांधी आगे हैंजविपक्ष का सारा 'स्पेस' उनका है। सत्तापक्ष, विपक्ष को यह कहकर लज्जित करना चाहता है कि उसका ऐसा अड़ियल व्यवहार गैरजिम्मेदाराना है। एक ओर वह कहता है कि संविधान खतरे में है, तो दूसरी ओर संसद न चलने देकर वह संविधान को ही खतरे में डालता है। सरकार को रक्षात्मक देख विपक्ष अपनी करता रहता है कि संसद चलाना सत्तापक्ष का कामज हमारा काम विरोध करना है। पहले विपक्ष की तीन मांगें मानो कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, छात्रों से माफी मांगें और नीट पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले विद्यार्थियों के परिवारों को एक करोड़ रुपए का मुआवजा दें। फिर 'काकरोच जनता पार्टी' की एक और मांग कि प्रदर्शनकारियों पर केस वापस लें। उधर, 'काकरोच जनता पार्टी' के कुछ नेताओं के लिए 'भूख हड़ताल' भारी पड़ी। एक 'काकरोच' ने भूख हड़ताल के दौरान 'बर्गर' खाया और फिर टीवी चैनलों को स्वयं बताया कि खाया। इसके बाद वह 'काकरोच जनता पार्टी' के प्रवक्ता पद से बाहर हो गया, लेकिन वह बंदा भी गजब कि जाते-जाते कह गया कि 'उन्होंने' भी कचौड़ी खाई है। 'काकरोच' के नेता उतनी सुर्खियों में नहीं दिखते, जितने कि सोनम वांगचुक या विपक्ष के नेता हैं। संसद में हर दिन अब सिर्फ लंबा 'स्थगन' है! संसद स्थगित, लेकिन बाहर मकर द्वार पर विपक्ष का लगभग हर रोज प्रदर्शन। फिर एक दिन सत्तापक्ष के सांसदों का मकर द्वार पर जवाबी प्रदर्शनज। मानसून सत्र के पहले दिन ही 'काकरोच जनता पार्टी' का संसद की ओर 'कूच' का एलान। पुलिस द्वारा रास्ते बंद करना, लेकिन बढ़ती भीड़ बेकाबू, फिर पत्थरबाजी और पुलिस का बल प्रयोग। ऐसे दृश्य दिल्ली सहित कई बड़े शहरों में देखे गए। चैनलों पर सब कुछ का सीधा प्रसारणज कुछ चैनलों के पत्रकार भी प्रदर्शनकारियों का निशाना बनेज्बहसें विपक्ष के नेताओं और प्रदर्शनकारियों के पक्ष में झुकती हुई..। उधर, पुलिस का कथन कि प्रदर्शन में बहुत से बाहरी तत्त्व भी शामिल दिखते हैंज वे अपने चेहरों को छिपाकर, हेल्मेट पहनकर पत्थर चलाते हैं, कुछ तलवारें भी लहराते हैं, वे पुलिस या सार्वजनिक संपत्ति को निशाना बनाते हैं। कुछ एंकर और चर्चकों के लिए कथित 'जेन-जी पीढ़ी' का आचरण आपत्तिजनक, कइयों को संदेह कि ये विद्यार्थी हैं या असामाजिक तत्त्व? ये किसी विदेशी 'टूलकिट' से प्रेरित हैं और मांग कि पुलिस सख्ती बरते इनको हटाए। इस बीच, बॉलीवुड अभिनेताओं समेत कई हस्तियां छात्रों के समर्थन में खड़ी हो गईं! फिर एक शाम सबसे बड़े विपक्षी दल का प्रधानमंत्री आवास के पास प्रदर्शन और नारे।

राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इसका नेतृत्व करते हुए। एक मंत्री का राहुल से मिलकर बातचीत करना कि विपक्षी नेता सुरक्षा की दृष्टि से इस संवेदनशील इलाके से हट जाएंज सरकार बातचीत करने को तैयार है। जब नहीं हटे, तो पुलिस ने जबरन हटाया। कई चर्चक कहिन कि विपक्ष एक बार फिर सरकार को हिलाकर निकल गया। उधर, गुरुवार की रात को प्रधानमंत्री ने एक नया एलान किया कि प्रश्नपत्र लीक मामलों में दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए त्वरित अदालतें बनाई जाएंगी, सख्त कानून लाएंगे, जिसमें सजा की अवधि और जुर्माने को बढ़ाने के प्रावधान होंगे। जब पूछा गया कि क्या विपक्ष नए कानून का समर्थन करेगा, तो जवाब आया कि पहले संबंधित विधेयक को देखेंगे, तब बताएंगे। इसी बीच, सोनम वांगचुक की ओर से 26 दिन पुरानी भूख हड़ताल को समाप्त करने की खबर आई। साथ ही यह खबर भी आई कि किसी 'न्यूट्रल' जगह पर 'काकरोच जनता पार्टी' के नेता सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार हैं।

विश्वासघात के बाद हार नहीं मानें, वो समय खुद को फिर से गढ़ने का होता है

(आकांक्षा दीक्षित)

टूटने के बाद अधिकांश वस्तुएं टुकड़ों में बंट कर बिखर जाती हैं। जब उनको किसी चिपकाने वाले पदार्थ से जोड़ा जाता है, तो वे अपना मूल स्वरूप बदल देती हैं, क्योंकि टूटने के बाद जुड़ने में ऐसा होना स्वाभाविक है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है। जब अप्रत्याशित विश्वासघात या जीवन के संघर्षों के झंझावात किसी व्यक्ति को भीतर तक तोड़कर रख देते हैं, तो उस एक कमजोर क्षण में आात्मघात सबसे पहला और आसान उपाय लगता है। मगर क्या वास्तव में यह समाधान है? क्या किसी धोखेबाज, किसी विपरीत परिस्थिति या किसी कठिन दौर के आगे घुटने टेककर अपनी जीवन-लीला समाप्त कर लेना न्यायसंगत है? बिल्कुल नहीं। जब चोट पहुंचाने वाले, धोखा देने वाले लोग दुनिया में मुस्कुरा रहे हैं और खुश हैं, तब अपनी ही अनमोल जान को दांव पर लगा देना किसी भी समस्या का सही जवाब नहीं हो सकता। यह समय बिखरने का नहीं, बल्कि खुद को पहले से ज्यादा मजबूत बनाकर परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करने का है। जापान में एक पुरानी परंपरा है 'किंत्सुगी'। जब मिट्टी या चीनी के बर्तन टूट जाते हैं, तो जापानी लोग उन्हें फेंकते नहीं हैं। वे उन टूटे हुए टुकड़ों को सोने, चांदी या प्लैटिनम मिश्रित लाख से जोड़ते हैं। परिणाम यह होता है कि वह बर्तन पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाता है और उसकी दरारें सोने की चमक से जगमगा उठती हैं। वह बर्तन अपनी कमियों को छिपाता नहीं, बल्कि उन्हें गर्व से दिखाता है। इंसानी जिंदगी भी ऐसी ही है। विश्वासघात या असफलता से जब हमारा दिल टूटता है, तो हमारे व्यक्तित्व में दरारें आती हैं। लेकिन जब हम धैर्य, आत्म-प्रेम और साहस के अवलेह से खुद को दोबारा जोड़ते हैं, तो हमारा नया

मनोविज्ञान में एक महत्त्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसे 'पोस्ट-ट्रामेटिक ग्रोथ' यानी आघात-पश्चात विकास कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक डा रिचर्ड टेडेशी और लारेंस कैलहौन के शोध बताते हैं कि जीवन में गहरे संकट, मानसिक आघात या गंभीर विश्वासघात का सामना करने वाले अधिकतर लोग केवल अवसाद में ही नहीं डूबते, बल्कि एक समय के बाद वे मानसिक रूप से पहले से कहीं अधिक सुदृढ़ हो जाते हैं। इस संकट से गुजरने के बाद लोगों में रिश्तों की बेहतर समझ विकसित होती है, वे सही और गलत लोगों की पहचान करना सीख जाते हैं और उन्हें अपनी उस आंतरिक शक्ति का अहसास होता है, जिससे वे पहले अनजान थे। जब कोई हमें धोखा देता है, तो वह हमारे भरोसे को तोड़ता है। हमारा जीवन किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं हो सकता।

स्वरूप पहले से कहीं ज्यादा निखर कर सामने आता है। हमारा मूल स्वरूप बदल जरूर जाता है- हम अधिक परिपक्व और संजीदा हो जाते हैं- लेकिन हमारी आंतरिक मजबूती कई गुना बढ़ जाती है। मनोविज्ञान में एक महत्त्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसे 'पोस्ट-ट्रामेटिक ग्रोथ' यानी आघात-पश्चात विकास कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक डा रिचर्ड टेडेशी और लारेंस कैलहौन के शोध बताते हैं कि जीवन में गहरे संकट, मानसिक आघात या गंभीर विश्वासघात का सामना करने वाले अधिकतर लोग केवल अवसाद में ही नहीं डूबते, बल्कि एक समय के बाद वे मानसिक रूप से पहले से कहीं अधिक सुदृढ़ हो जाते हैं। इस संकट से गुजरने के बाद लोगों में रिश्तों की बेहतर समझ विकसित होती है, वे सही और गलत लोगों की पहचान करना सीख जाते हैं और उन्हें अपनी उस आंतरिक शक्ति का अहसास होता है, जिससे वे पहले अनजान थे। जब कोई हमें धोखा देता है, तो वह हमारे भरोसे को तोड़ता है। हमारा जीवन किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं हो सकता। मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक, आत्मघाती विचार एक 'अस्थायी मानसिक कोहरा' होते हैं।

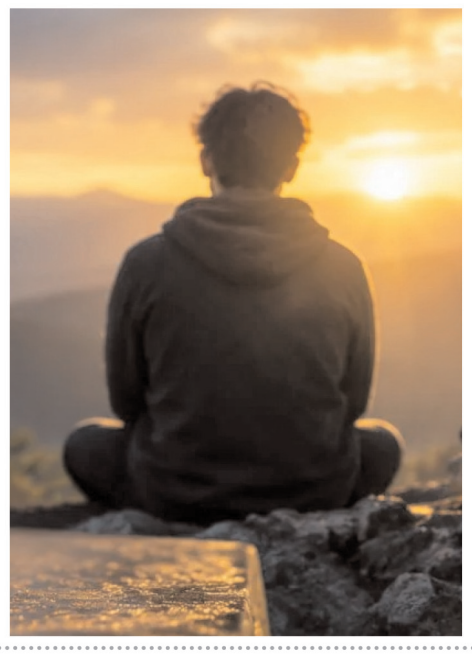

अगर उस एक कमजोर पल को धैर्य से पार कर लिया जाए, तो आगे की जिंदगी में सफलता की नई राहें खुलती हैं। इतिहास और वर्तमान ऐसे नायकों की कहानियों से भरा पड़ा है, जिन्होंने गहरे विश्वासघात और जीवन के झंझावातों को सहा, लेकिन हार मानने के बजाय इतिहास रच दिया। इस बात पर गहराई से विचार करना चाहिए कि जिसने हमें धोखा दिया, विश्वास का कत्ल किया, वह अपनी जिंदगी में मुस्कुरा रहा है, पार्टियां कर रहा है और आगे बढ़ चुका है। ऐसे में हमारे द्वारा उठाया गया कोई भी आत्मघाती कदम उसे दंड नहीं देगा, बल्कि उसे हमारे जीवन के अध्याय को हमेशा के लिए बंद करने का एक बहाना दे देगा। हमारी मृत्यु से सबसे ज्यादा दुख हमारे माता-पिता, सच्चे मित्रों और शुभचिंतकों को होगा, जिनका कोई दोष नहीं था। दोषी व्यक्ति को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए सबसे बड़ा प्रतिशोध यह नहीं है कि हम खुद को मिटा दें। सबसे बड़ा और खूबसूरत प्रतिशोध यह है कि हम खुद को इतना कामयाब, खुश और मजबूत बना लें कि हमें चोट पहुंचाने वाले लोग हमारी ऊंचाई को देखकर खुद अपनी नजरों में बौने साबित हो जाएं। अगर कोई वर्तमान में किसी ऐसे ही दौर से गुजर रहा है, जहां सब कुछ बिखरा हुआ लग रहा है, तो कुछ बातों को अपने जीवन का मंत्र बना लेना चाहिए। सबसे पहले, उस एक कमजोर पल को टाल दिया जाए, क्योंकि आत्महत्या का विचार अक्सर एक तीव्र और क्षणिक आवेग होता है। जब भी ऐसा महसूस हो, किसी विश्वसनीय मित्र, परिवार के सदस्य या हेल्पलाइन से बात करने की जरूरत है। जैसे शरीर बीमार होने पर हम डाक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही मन के बीमार होने या टूटने पर मनोचिकित्सक या काउंसलर की मदद लेना पूरी तरह सामान्य और जरूरी है। अपने भीतर की पीड़ा, गुबार, गुस्से और दुख को किसी रचनात्मक कार्य, करिअर या समाज सेवा में झोंक देना चाहिए। इतिहास गवाह है कि महानतम कला और सफलताएं गहरे दर्द की कोख से ही पैदा हुई हैं। इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि टूटने के बाद हमारा पुराना स्वरूप शायद वापस न आए, लेकिन यह नया रूप अधिक सतर्क, अधिक समझदार और कहीं अधिक शक्तिशाली होगा। जिंदगी एक अनमोल उपहार है, जिसे किसी भी विश्वासघाती या कठिन परिस्थिति की भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता। टूटना अंत नहीं है, बल्कि यह एक नए और अधिक मजबूत स्वरूप के निर्माण की शुरुआत है। जब चीनी मिट्टी का बर्तन सोने से जुड़कर पहले से ज्यादा कीमती बन सकता है, तो हम हाड़-मांस के जीवित इंसान हैं, जिसके भीतर अदम्य इच्छाशक्ति का वास है। याद रखना चाहिए कि झंझावात पेड़ की सूखी पत्तियों को गिराते हैं, उसकी जड़ों को मजबूत करते हैं। खुद को समेट कर, उठने, अपनी दरारों को अपने तजुर्बे का सोना बनाने और दुनिया को दिखा देने की जरूरत है कि हम बिखरने के लिए नहीं, बल्कि निखरने के लिए बने हैं।

शिक्षक बनने का सुनहरा अवसर, मावा मोदोल नि:शुल्क कोचिंग से शिक्षक भर्ती क्रैश कोर्स के लिए चयन परीक्षा आयोजित

नई उड़ान, मावा मोदोलजिला प्रशासन की अनूठी पहल:

कांकेर/मूक पत्रिका

विक्रम ठाकुर/:-जिला प्रशासन उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा युवाओं को शिक्षक एवं सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफलता दिलाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए मावा मोदोल निःशुल्क कोचिंग संस्थान के माध्यम से विशेष चयन परीक्षा का आयोजन किया गया। कलेक्टर नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर के निर्देशन तथा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हरेश मंडावी के मार्गदर्शन में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा यह परीक्षा आयोजित की गई।इस पहल का उद्देश्य जिले के उन युवाओं को गुणवत्तापूर्ण एवं निःशुल्क मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है, जो शिक्षक एवं सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं। इसके लिए सीटीईटी, सीजी-टीईटी उत्तीर्ण तथा बी.एड./डी.एड. अर्हताधारी अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे।चयन परीक्षा का आयोजन जिला मुख्यालय कांकेर स्थित मावा मोदोल केंद्र तथा विकासखंड भानुप्रतापपुर में किया गया। परीक्षा में कांकेर केंद्र से 170 तथा भानुप्रतापपुर केंद्र से 60, कुल 230 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। चयन परीक्षा के परिणाम 3 अगस्त तक जारी किए जाएंगे, जबकि 4 अगस्त से काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ कर मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की विशेष क्रैश कोर्स कक्षाएं संचालित की जाएंगी। जिला प्रशासन ने उन अभ्यर्थियों को भी राहत दी है जो किसी कारणवश निर्धारित तिथि पर परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को 3 अगस्त (सोमवार) 8 को संबंधित परीक्षा केंद्र में उपस्थित होकर पंजीयन कराने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने का अतिरिक्त अवसर दिया गया है। इन अभ्यर्थियों का चयन भी परीक्षा एवं काउंसलिंग के आधार पर किया जाएगा। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हरेश मंडावी ने बताया कि शिक्षक एवं सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा तक यह क्रैश कोर्स पूरी तरह निःशुल्क संचालित किया जाएगा। इसमें चयनित अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र भरने से लेकर परीक्षा के संपूर्ण पाठ्यक्रम का विषयवार अध्ययन कराया जाएगा। साथ ही नियमित टेस्ट, मूल्यांकन एवं विशेषज्ञ शिक्षकों के मार्गदर्शन के माध्यम से अभ्यर्थियों की तैयारी को मजबूत बनाया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक युवा भर्ती परीक्षा में सफल होकर शिक्षक बनने का सपना साकार कर सकें।

उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन अगामी माह में आयोजित होने वाली प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु प्रतिबद्ध है आने वाले दिनों में व्याख्याता भर्ती की प्रक्रिया होने पर उसकी भी तैयारी कराई जावेगी। इस पहल से ग्रामीण एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। निःशुल्क कोचिंग, नियमित अभ्यास एवं अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से अभ्यर्थियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और उनकी सफलता की संभावना भी मजबूत होगी।

इस पूरी चयन परीक्षा के संचालन एवं रूपरेखा तैयार करने में जिला शिक्षा अधिकारी रमेश कुमार निषाद तथा जिला मिशन समन्वयक (डीएमसी) नवनीत पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जिला प्रशासन ने सभी पात्र युवाओं से इस अवसर का लाभ उठाकर शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने और अपने उज्ज्वल भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाने की अपील की है।

प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज की अहम बैठक सम्पन्न, 23 अगस्त को होंगे जिला चुनाव

बेमेतरा/मूक पत्रिका

जिला मुख्यालय गुरु बालक दास स्मृति स्थल सतनाम धाम (पिकरी, बहुनवागांव रोड) में रविवार को प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज, जिला बेमेतरा की जिला कार्यकारिणी, वरिष्ठ, युवा एवं महिला प्रकोष्ठ की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन को और अधिक मजबूत एवं सक्रिय बनाने, समाजहित के विभिन्न मुद्दों पर प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने तथा आगामी संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।बैठक में समाज की शिक्षा, सामाजिक समानता, संगठनात्मक एकता, युवा सहभागिता एवं अधिकारों की रक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श हुआ। सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने समाज के सर्वांगीण विकास के लिए एकजुट होकर निरंतर कार्य करने का संकल्प लिया।बैठक का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज, जिला बेमेतरा के जिला स्तरीय चुनाव 23 अगस्त 2026 को आयोजित किए जाने का रहा। इस प्रस्ताव पर उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने सर्वसम्मति से अपनी सहमति प्रदान की।बैठक में जिला अध्यक्ष राजा लाल बंजारे ने संगठन के विस्तार, ब्लॉक स्तर तक गतिविधियों को सशक्त बनाने तथा समाज के प्रत्येक वर्ग की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया वही समाज के वरिष्ठजनों, युवाओं एवं मातृशक्ति से आगामी चुनाव एवं संगठनात्मक कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया गया। बैठक के अंत में संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि समाज की प्रगति का आधार मजबूत संगठन और आपसी एकता है। जिला अध्यक्ष राजा लाल बंजारे ने सभी समाजजनों से एकजुट होकर संगठन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकल्प लेने की अपील की।

स्काउटिंग की पहचान है स्कार्फ - के.आर. सिन्हा, सशक्त, समृद्ध राष्ट्र निर्माण हेतु स्काउटिंग से जुड़े हर युवा

छुरा।।स्वावलम्बन के पर्याय, आयुर्वेदरत्न, स्काउट मास्टर के.आर. सिन्हा ने वर्ल्ड स्कार्फ डे की बधाई देते हुए लोगों को स्काउटिंग गतिविधियों से जुड़ने का आह्वान किया। सिन्हा ने कहा कि स्काउटिंग एक शैक्षिक आंदोलन है जो युवाओं को आत्म अनुशासन, समाज सेवा और देशभक्ति के मूल्यों को विकसित करने में मदद करता है। स्काउटिंग का मूल उद्देश्य युवाओं को जिम्मेदार नागरिक बनाना है। स्काउटिंग बालचरों को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से विकसित करता है। सिन्हा ने आगे कहा कि स्कार्फ स्काउटिंग की पहचान है। हमें एकता, अनुशासन और सेवा के पथ पर अग्रसर करता है। विश्व के 224 देश में स्काउटिंग गतिविधि संचालित है, जिसके 54 मिलियन से अधिक युवा और वयस्क सदस्य हैं।

भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के पूर्व जिला प्रशिक्षण आयुक्त, स्काउट मास्टर, योगविद अर्जुन धनंजय सिन्हा ने कहा कि स्काउटिंग एक वैश्विक आंदोलन है जो युवाओं को सक्रिय बनाने और अपने समुदाय में सकारात्मक बदलाव लाने हेतु प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के स्काउट्स द्वारा विश्व स्कार्फ दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, यह 1907 में पहले स्काउट शिविर की याद दिलाता है। स्कार्फ, स्काउटिंग के प्रति प्रतिबद्धता एवं विशेष लगाव का प्रतीक है। यह स्काउटिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। स्कार्फ पहनकर स्काउट्स अपने अनुभव पर गर्व महसूस करता है।

अलग-अलग रंग के स्कार्फ पहनने की विशेष परंपरा है। विशिष्ट रंगों से स्काउटिंग में आसीन पदों का भी पहचान होता है। स्कार्फ को पहनने के साथ-साथ आपातकालीन परिस्थितियों में पट्टी या रस्सी के रूप में प्राथमिक उपचार में उपयोग कर सकते हैं। इसको वागल या गांठ के साथ बांधा जाता है, जिससे आकर्षण में वृद्धि होता है। स्काउटिंग एक संपूर्ण जीवन शैली है जिससे जुड़कर एक जिम्मेदार नागरिक बनकर राष्ट्र सेवा कर सकते हैं।

करपावंड-भानपुरी-उमरकोट मुख्य मार्ग बदहाल, गड्ढों और आवारा मवेशियों से बढ़ा हादसों का खतरा

बजगदलपुर/मूक पत्रिका

पवन कुमार नाग -जगदलपुर से करपावंड, भानपुरी होते हुए ओडिशा के उमरकोट को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग इन दिनों बदहाल स्थिति में है। सड़क पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं, जबकि दिन-रात आवारा मवेशियों का जमावड़ा भी लगा रहता है। इससे इस मार्ग से गुजरने वाले हजारों वाहन चालकों और यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर संकट पैदा हो गया है।यह मार्ग बस्तर और ओडिशा के बीच आवागमन का प्रमुख संपर्क मार्ग है, जहां प्रतिदिन यात्री बसें, एंबुलेंस, स्कूल वाहन, भारी मालवाहक ट्रक तथा अन्य छोटे-बड़े वाहन आवाजाही करते हैं। सड़क की जर्जर हालत के कारण वाहन चालकों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के मौसम में गड्ढों में पानी भर जाने से उनकी गहराई का अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। समस्या को और गंभीर बना रहे हैं सड़क पर दिन-रात बैठे आवारा मवेशी। विशेषकर रात के समय पर्याप्त रोशनी नहीं होने के कारण मवेशी समय पर दिखाई नहीं देते, जिससे दोपहिया और चारपहिया वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार हादसे होते-होते बचे हैं, लेकिन अब तक संबंधित विभाग की ओर से कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है।

क्षेत्रवासियों और राहगीरों ने लोक निर्माण विभाग (क्क्ष्ठ) एवं जिला प्रशासन से मांग की है कि मार्ग की तत्काल मरम्मत कर गड्ढों को भरा जाए तथा आवारा मवेशियों को सड़क से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर भेजने की व्यवस्था की जाए। उनका कहना है कि यदि समय रहते आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में कोई बड़ा सड़क हादसा हो सकता है, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग और प्रशासन की होगी।

सफलता की कहानी: धान से ग्राफ्टेड बैंगन तक बदली किसान कंदर्प नायक की तकदीर

गरियाबंद। देवभोग विकासखण्ड के ग्राम करचिया के प्रगतिशील किसान श्री कंदर्प नायक ने आधुनिक उद्यानिकी तकनीकों को अपनाकर खेती में नई सफलता हासिल की है। पहले वे पारंपरिक रूप से धान की खेती करते थे, जिसमें लागत अधिक और आय कम होने के कारण परिवार का पालन-पोषण और बच्चों की शिक्षा में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लगभग 12 वर्ष पूर्व उद्यानिकी विभाग के संपर्क में आने के बाद उन्होंने विभागीय योजनाओं की जानकारी प्राप्त की और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत ड्रिप सिंचाई, मल्चिंग तथा ग्राफ्टेड बैंगन की खेती शुरू की। आधुनिक तकनीकों के उपयोग से पानी की बचत हुई, पौधों में रोग कम लगे तथा उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। इससे खेती की लागत घटी और आय में कई गुना बढ़ोतरी हुई। वर्तमान में श्री नायक 1 एकड़ क्षेत्र में ग्राफ्टेड बैंगन की खेती कर रहे हैं। उद्यानिकी विभाग द्वारा समय-समय पर तकनीकी प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन मिलने से उन्हें खेती में लगातार बेहतर परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। उद्यानिकी खेती अपनाकर और अधिक लाभ प्राप्त कर वे अपने बच्चे को आईसीएआर, नई दिल्ली में उच्च शिक्षा दिला रहे हैं।

छुरा के वार्ड क्रमांक 06 में सीसी रोड के भूमिपूजन के साथ विकास कार्य का शुभारंभ

छुरा ।नगर पंचायत छुरा के वार्ड क्रमांक 06 (गादीकोट) में छत्तीसगढ़ शासन से प्राप्त अधोसंरचना मद के अंतर्गत सीसी रोड निर्माण कार्य का भूमिपूजन कार्यक्रम शनिवार को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, स्थानीय नागरिकों एवं कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही।

भूमिपूजन के साथ वार्ड में बहुप्रतीक्षित सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष लुकेश्वरी निषाद ने कहा कि इस निर्माण कार्य से क्षेत्रवासियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी तथा बरसात के दिनों में कीचड़ और जलभराव जैसी समस्याओं से काफी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि नगर के समग्र विकास के लिए विभिन्न आधारभूत सुविधाओं का विस्तार लगातार किया जा रहा है।कार्यक्रम के दौरान नगरवासियों ने विकास कार्य प्रारंभ होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए शासन एवं जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया। स्थानीय लोगों ने विश्वास जताया कि सड़क निर्माण पूर्ण होने के बाद वार्ड की तस्वीर बदलेगी और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस अवसर पर नगर पंचायत उपाध्यक्ष समीम खान, सभापति चित्ररेखा ध्रुव,रजनी लहरे, बलराज पटेल,गरिमा ध्रुव,पार्षद देवसिंह नेताम,हरीश यादव,सलीम मेमन, रामजी दीवान, शांतनु देवांगन,यामीन(ट्रांसजेंडर), दीप्ति यादव, एल्डरमैन तुलाराम साहू ,सफर सचदेव, धर्मेंद्र चंद्राकर ,अजय दीक्षित रामाधार यादव,निखिल साहू ,पीयूष सिन्हा, नारायण पटेल, भवानीशंकर सेन, तुलसीराम साहू, संतोष ध्रुव,कोपेश्वर साहू, अमान उल्ला,विजय देवांगन एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे ।

आईएसबीएम विश्वविद्यालय में 'नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान' का सफल आयोजन

भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के निर्देशानुसार आयोजित हुआ जागरूकता कार्यक्रम

छुरा। आईएसबीएम विश्वविद्यालय, नवापारा (कोसमी), छुरा में ÷नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत - संकल्प अभियान÷के अंतर्गत एक जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया।कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना, उन्हें स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना तथा नशामुक्त एवं सशक्त युवाओं के माध्यम से विकसित भारत के निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना था। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की तथा नशे से दूर रहने और समाज में नशा-मुक्ति का संदेश फैलाने का सामूहिक संकल्प लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. बी.पी. भोल ने कहा कि, ÷विकसित भारत का निर्माण स्वस्थ, शिक्षित, जागरूक और जिम्मेदार युवाओं के बिना संभव नहीं है।÷ वहीं संयुक्त कुलसचिव डॉ. रानी झा ने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे नशामुक्त रहकर आपसी सौहार्द बनाए रखें तथा अपने सपनों को साकार करने के लिए सतत प्रयास करें।इसके पश्चात विज्ञान संकाय की सह-प्राध्यापिका डॉ. पूनम वर्मा ने नशा-मुक्ति का संदेश देते हुए सभी उपस्थितजनों को सामूहिक संकल्प एवं शपथ दिलाई।इस अवसर पर ऑनलाइन माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नशामुक्ति एवं जन- जागरूकता संबंधी संबोधन का सीधा प्रसारण भी किया गया। उपस्थित अधिकारियों, शिक्षकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों ने उनके विचारों को ध्यानपूर्वक सुना तथा नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए किए जा रहे प्रयासों से प्रेरणा प्राप्त की।कार्यक्रम के संयोजक एवं छात्र कल्याण अधिष्ठाता डॉ.ओमप्रकाश साहू ने कहा कि, ÷युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं।यदि युवा नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं तो इसका प्रभाव केवल उनके व्यक्तिगत जीवन पर ही नहीं, बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र के

बस्तर को हरा-भरा बनाने शहरभर में किया 1000 पौधा वितरण

'जन सहयोग' और फॉरेस्ट विभाग की साझा मुहिम: घड़ी चौक से बस स्टैंड तक गूंजा हरियाली का संदेश

कांकेर/मूक पत्रिका

विक्रम ठाकुर:-काँकेर अपने पूर्व निर्धारित वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार आज प्रातः समाज सेवी संस्था ÷जन सहयोग÷ द्वारा शहर में पौधा वितरण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न किया गया, जिसमें जन- सहयोग के सदस्यों के अलावा काँकेर वन विभाग के की स्टॉफने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। सुबह 7:00 बजे शहर की उत्तरी सीमा स्थित घड़ी चौक से प्रारंभ होकर संस्था के अध्यक्ष अजय पप्पू मोटवानी के नेतृत्व में जुलूस ने शहर के मुख्य मार्ग होते हुए बस स्टैंड में कार्यक्रम को परिणति तक पहुंचाया। राह में मिलने वाले समस्त नागरिक सज्जनों को सम्मान सहित पौधे प्रदान किए गए और उनसे विनम्र प्रार्थना की गई कि न केवल अपने घर आंगन में पौधा रोपण करें बल्कि उसकी सुरक्षा भी करें क्योंकि हमें न केवल पेड़ लगाने हैं बल्कि अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं क्योंकि हमारे बस्तर अंचल में बीते हुए समय में लाखों पेड़ विकास कार्यक्रमों की बलि चढ़ गए हैं। लाखों कीमती वृक्ष चोर तस्करों द्वारा नष्ट कर अवैध रूप से बेच दिए गए हैं। वितरण किए गए पौधों में फलदार तथा फूलदार हर प्रकार के पौधे थे जिन्हें लोगों की पसंद के अनुसार भी प्रदान किया गया। वन विभाग के डीएफओ, रौनक गोयल साहब द्वारा अपने विभाग की ओर से 1000 पौधे प्रदान किए गए। वन विभाग के अमले द्वारा पौधा वितरण कार्य में भी ÷जन सहयोग÷ संस्था से सक्रिय सहयोग किया गया। जिनमें वन मंडल अधिकारी रौनक गोयल साहब के अलावा अरुण कुमार ठाकुर परिक्षेत्र सहायक काँकेर, विमल ठाकुर परिक्षेत्र सहायक मर्दा पोटी, चैन सिंह परिक्षेत्र सहायक पुसवाड़ा, परिक्षेत्र सहायक पीढ़ापाल, सरस्वती तारम वनपाल, निरूपा वनपाल, सकीता नाग वनरक्षक, मेघा यादव वनरक्षक, प्रकाश मंडावी वनरक्षक राजवीर दुग्गा, पुनेशयादव वनरक्षक, दीपक भंडारी सुरक्षा श्रमिक, मनोज श्रीवास्तव वाहन चालक, सुनील यादव सुरक्षा श्रमिक, नंदलाल यादव, मुकेश यादव, बंटी यादव, दीपक देहारी, जन सहयोग की टीम में अध्यक्ष अजय पप्पू मोटवानी के अलावा पूर्व सैनिक टी के जैन, धर्मेंद्र देव, दिलीप कुमार गुप्ता, संजय मंशानी, सागर देव, ओंकार देव, आशुतोष देव तथा शैलेंद्र देहारी, अजय पांडे, आदि नौजवानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अध्यक्ष अजय पप्पू मोटवानी ने बताया कि ÷जन सहयोग ÷के उद्देश्यों में पर्यावरण भी एक प्रमुख उद्देश्य है, जिस पर हम पिछले दो दशकों से कार्य कर रहे हैं। आज के युग में प्रदूषण को देखते हए न केवल बस्तर अंचल बल्कि समस्त विश्व में पेड़ लगाने तथा हरियाली बढ़ाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है अन्यथा मानव स्वास्थ्य ही नहीं, मानव जीवन पर भी संकट उत्पन्न हो सकता है। आज के पौधा-वितरण कार्यक्रम की समस्त जिले में प्रशंसा की जा रही है।

200 से अधिक विभूतियों के सम्मान से रायगढ़ में शिक्षा और समाजसेवा का हुआ संगम

रायगढ़/मूक पत्रिका

रायगढ़ की धरा पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक ऐसा ऐतिहासिक दृश्य देखने को मिला, जिसने शिक्षा, पर्यावरण, राजनीति और समाजसेवा के क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम कर दी। 'नव निर्माण संकल्प समिति, रायगढ़' एवं 'दैनिक क्रांतिकारी संकेत' के संयुक्त तत्वावधान में नगर निगम ऑडिटोरियम (पंजरी प्लांट) में आयोजित गरिमामयी 'गुरु सम्मान समारोह' कार्यक्रम संयोजक रामचन्द्र शर्मा के कुशल मार्गदर्शन में आयोजित इस गरिमामय समारोह ने सामाजिक समरसता और एकजुटता का एक अभूतपूर्व संदेश दिया। शहर और ग्रामीण अंचलों की 200 से अधिक विशिष्ट हस्तियों, शिक्षकों, पर्यावरणविदों और समर्पित सामाजिक कार्यकर्ताओं को शॉल, स्मृति चिह्न (मोमेंटो) एवं प्रशस्ति पत्र भेंट कर भव्य नागरिक अभिनंदन किया गया।

मंच पर उतरा दिग्गजों का कारवां- समारोह में रायगढ़ और आसपास के क्षेत्रों के शीर्ष राजनीतिक, प्रशासनिक व सामाजिक चेहरे एक मंच पर नज़र आए। जिसमें मुख्य रूप से उमेश नंदकुमार पटेल (विधायक, खरसिया), लालजीत सिंह राठिया (विधायक, धर्मजयगढ़), नगेंद्र नेगी (अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण), शाखा यादव (अध्यक्ष, शहर कांग्रेस कमेटी), महेंद्र यादव अधिवक्ता भाजपा नेता , सलीम नियारिया (नेता प्रतिपक्ष, नगर निगम रायगढ़), फादर सुशील टोप्पो (प्रिंसिपल, सेंट माइकल स्कूल), चंद्रप्रकाश देवांगन (वरिष्ठ शिक्षाविद), अबरार हुसैन (संचालक, सहयोग करियर अकेडमी), सुभाष त्रिपाठी और अनिल पांडेय (वरिष्ठ पत्रकार), दीपक पांडेय (वरिष्ठ समाजसेवी) एवं अनिल शुक्ला (पूर्व अध्यक्ष, रायगढ़ शहर) सहित अनेक गणमान्य नागरिकों ने मंच साझा कर सम्मानित होने वाली विभूतियों का उत्साहवर्धन किया

गुरु ही गढ़ते हैं समाज का भविष्य : उमेश पटेल-कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खरसिया विधायक उमेश पटेल ने कहा कि गुरु केवल किताबी ज्ञान नहीं देते, बल्कि वे समाज के चरित्र, संस्कार और भावी दिशा का निर्माण करते हैं। निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे शिक्षकों और समाजसेवियों को सम्मानित करना पूरे रायगढ़ के लिए गर्व की बात है। वहीं धर्मजयगढ़ विधायक लालजीत सिंह राठिया ने कहा कि राजनीतिक और सामाजिक समरसता का यह अद्भुत संगम रायगढ़ की गंगा-जमुनी तहज़ीब को दर्शाता है। शिक्षक समाज के सच्चे पथप्रदर्शक हैं। रामचंद्र शर्मा, दीपक मंडल और नव निर्माण संकल्प समिति की पूरी टीम द्वारा आयोजित यह महाकुंभ अपने आप में ऐतिहासिक है।

टीम वर्क की मिसाल : रामचन्द्र शर्मा ने जताया आभार-समारोह की ऐतिहासिक सफलता पर मंच से आभार व्यक्त करते हुए संयोजक रामचन्द्र शर्मा भावुक नज़र आए। उन्होंने कहा, यह मेरी अकेले की सफलता नहीं, बल्कि रायगढ़ की एकजुटता की जीत है। आप सभी सहयोगियों और पधारे हुए शिक्षकों के बिना मैं और यह आयोजन दोनों अधूरे थे। उन्होंने विशेष रूप से अपनी टीम के साथियों में आशीष रंगारी, चतुर्भुज पटेल, प्रमोद पटेल, राजेंद्र चौरसिया, भुवन पटेल, प्रकाश सिंह, विनोद चौहान, घनश्याम पटेल, नरेंद्र पटेल, भावना शर्मा, सुशील गुप्ता, दीपक मंडल (सचिव, नव निर्माण संकल्प समिति), अनिल प्रधान, मुरलीधर गुप्ता, सुमन प्रधान तथा दैनिक क्रांतिकारी संकेत के प्रतिनिधि मंडल व संपूर्ण स्कूल स्टाफ के प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित किया।

फूड इंस्पेक्टर की नौकरी दिलाने के नाम पर ?1.91 लाख की ठगी, आरोपी दुर्ग-भिलाई से गिरफ्तार

जगदलपुर/मूक पत्रिका

बस्तर पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक आरोपी को दुर्ग-भिलाई से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी ने मंत्रालय रायपुर में अच्छी पहचान होने का झांसा देकर फूड इंस्पेक्टर के पद पर नौकरी लगाने के नाम पर प्रार्थी से ?1.91 लाख की ठगी की थी। घटना के बाद आरोपी मोबाइल बंद कर फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने कई बार दबिश देने और मुखबिर की सूचना के आधार पर उसके भिलाई स्थित घर से हिरासत में लिया।गिरफ्तार आरोपी की पहचान लारेन्स एन्थोनी कुज (57 वर्ष), पिता एन्थोनी कुज, निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, ब्लॉक नंबर 17/07, औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला दुर्ग के रूप में हुई है।पुलिस के अनुसार, प्रार्थी विनोद पानीग्राही (43 वर्ष) निवासी आसना स्कूल पारा, जगदलपुर ने थाना कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका पूर्व

परिचित लारेन्स एन्थोनी कुज मंत्रालय में अपनी पहुंच का दावा कर फूड इंस्पेक्टर की नौकरी दिलाने का आश्वासन देता रहा। आरोपी ने 24 जुलाई 2022 से 20 सितंबर 2024 के बीच गूगल पे और चेक के माध्यम से कुल ?1,91,500 अपने खाते में जमा कराए, लेकिन न तो नौकरी दिलाई और न ही राशि लौटाई। शिकायत के आधार पर थाना कोतवाली में धारा 318(4) भारतीय न्याय संहिता (ब्नहस्) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर, नगर पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार धोत्रे के पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी निरीक्षक लीलाधर राठौर के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर आरोपी की तलाश की गई।पुलिस टीम ने आरोपी के संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी। आरोपी घर से बाहर रहकर गिरफ्तारी से बचने का प्रयास कर रहा था, लेकिन मुखबिर की सूचना पर उसे भिलाई स्थित उसके निवास से हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने गूगल पे के माध्यम से राशि प्राप्त करना स्वीकार किया। पुलिस ने उसके कब्जे से मोबाइल फोन जब्त कर साक्ष्य के रूप में अपने कब्जे में लिया। पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद आरोपी को 2 अगस्त 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अधिकारी-कर्मचारीःनिरीक्षक लीलाधर राठौरउपनिरीक्षक अरुण मरकामप्रधान आरक्षक भूपेंद्र पैकराप्रधान आरक्षक राजू टोप्पो, विनोद चांदने, मोहन कश्यप आरक्षक उज्जवल सिंह, रंगलाल खरे, त्रिनाथ कश्यप एवं तामेश्वर चंद्राकर।

पंडित रविशंकर शुक्ल एवं विद्याचरण शुक्ल की जयंती पर कांग्रेसजनों ने किया स्मरण

नवापारा राजिम। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गोबरा-नवापारा द्वारा अविभाजित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल की जयंती पर श्रद्धांजलि एवं स्मरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने दोनों दिवंगत नेताओं के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके योगदान को नमन किया।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रामा यादव ने कहा कि पंडित रविशंकर शुक्ल ने प्रदेश के विकास की मजबूत नींव रखी, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल ने जनसेवा, लोकतांत्रिक मूल्यों और संगठन को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं के आदर्श, विचार और कार्य आज भी समाज एवं युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत हैं। इस अवसर पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष धनराज मध्यानी, पूर्व उपाध्यक्ष चतुर जगत, पार्षद अजय साहू एवं अर्जुन साहू, हेमंत साहनी, टिकेश्वर गिलहरे, रामरतन निषाद, तरुण कंसारी, रेखा तिवारी, निर्माण यादव, शंकर साहू, अजय गाड़ा, विक्की साहू, डॉ. रामकुमार शर्मा, बीरबल राजपूत, विजय तारक सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

200 करोड़ का 'अमृत' और बूंद-बूंद को तरसते रायगढ़वासीः वार्ड 14 और 16 में केवल 20 मिनट सप्लाई!

24 घंटे पानी का वादा फुस्स, 200 करोड़ की योजना में सिर्फ 20 मिनट सप्लाई!

रायगढ़ /मूक पत्रिका

शहर में 200 करोड़ रुपये की लागत से शुरू हुई अमृत मिशन योजना अब सफेद हाथी साबित हो रही है। योजना शुरू करते वक्त शहरवासियों को 24 घंटे साफ पानी देने का बड़ा भरोसा दिया गया था। लेकिन धरातल पर दावों की पोल खुल चुकी है। शहर के वार्ड क्रमांक 14 और 16 के लोग आज भी मूलभूत पेयजल सुविधा के लिए तरस रहे हैं।इन वार्डों में अमृत मिशन के तहत रोजाना सिर्फ 15 से 20 मिनट ही पानी की सप्लाई हो रही है। इतने कम समय में एक सामान्य परिवार की दैनिक जरूरतें भी पूरी नहीं हो पातीं। योजना लागू होते ही नगर निगम ने पुराने बोरिंग कनेक्शन काट दिए थे। अब पर्याप्त पानी न

मिलने से परेशान लोग दोबारा अवैध रूप से बोर कनेक्शन जोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। समस्या से जूझ रहे वार्डवासियों ने नगर निगम से लेकर 'सुशासन तिहार' के शिविर में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के करीब डेढ़ महीने बाद निगम की टीम जांच के लिए मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह जांच सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह गई। मौके पर समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। दूसरी ओर, नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी अपनी कमियां छुपाने के लिए बिजली की समस्या का बहाना बना रहे हैं। जल विभाग के सब इंजीनियर प्रभारी सूरज देवांगन के मुताबिक, सुबह 1 घंटे पानी दिया जा रहा है। शाम को बिजली आपूर्ति बाधित होने से ओवरहेड टैंक से सप्लाई प्रभावित होती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस तकनीकी खामी का स्थायी समाधान अब तक क्यों नहीं निकाला गया?मामले में वार्डवासी लक्ष्मीकांत दुबे का कहना है कि डेढ़ महीने बाद आई निगम टीम सिर्फ खानापूर्ति करके चली गई। वहीं रहवासी अभिषेक पांडे और सुभाष मजूमदार ने बताया कि 24 घंटे पानी मिलने का दावा पूरी तरह झूठा साबित हुआ है। बिजली गुल होते ही मोहल्ले में पानी के लिए हाहाकार मच जाता है। 200 करोड़ खर्च होने के बाद भी जनता का रोज पानी के लिए संघर्ष करना प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

रायपुर जिला से शिक्षक गणेशराम एवं नेमेश्वर साहू प्रशिक्षण हेतु मध्यप्रदेश रवाना

आरंग । पूर्व माध्यमिक विद्यालय चपरीद के ऊर्जावान शिक्षक नेमेश्वर साहू तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालय तुलसी के शिक्षक गणेशराम साहू राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छ. ग द्वारा जारी आदेशानुसार प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में विद्यालय की भूमिका विषय पर प्रशिक्षण हेतु 2 अगस्त को ट्रेन से सी. सी. आर. टी दमोह म. प्र के लिए रवाना हो गए दस दिवसीय इस आवासीय प्रशिक्षण हेतु छत्तीसगढ़ से दस शिक्षकों का चयन किया गया है जिसमें जिला स्तर से सुदूर ग्रामीण अंचल से नेमेश्वर साहू व गणेश प्रसाद साहू का इस कार्यशाला में शामिल होना विकासखंड आरंग एवं जिला रायपुर के लिए निश्चित ही गौरव का विषय है इस कार्यशाला का आयोजन 3 अगस्त से 12अगस्त तक किया जा रहा है इस उपलब्धि पर बी आर सी सी आरंग सुरेन्द्र सिंह चंद्रसेन, शिक्षक कल्याण संघ प्रवक्ता पं छत्रधर दीवान, अध्यक्ष हरीश दीवान, प्रफुल्ल कुमार माँझी, ईश्वर कुमार साहू, राजकुमार दीपक, गणपत प्रसाद साहू, युवराम साहू, हेमंत चंद्राकर, छोटूराम साहू ,व्याख्याता निर्मला पाण्डेय आदि ने उक्त शिक्षकों को बधाई व शुभकामनाएं प्रेषित की है।

गोठ-बात में उठा गैस वितरण का मुद्दा, सभी 17 वार्डों में आसान होगी एलपीजी की उपलब्धता

आरंग। नगर पालिका परिषद द्वारा आयोजित गोठ-बात कार्यक्रम के तहत अवकाश दिवस शनिवार 1 अगस्त को पुराना नगर पालिका भवन के कक्ष में नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. संदीप जैन ने सत्कार गैस एजेंसी के संचालक गुरमीत सिंह होरा के साथ बैठक कर नगरवासियों को बेहतर और सुगम गैस वितरण व्यवस्था उपलब्ध कराने को लेकर विस्तृत चर्चा की।बैठक में निर्णय लिया गया कि नगर के सभी 17 वार्डों में एलपीजी गैस सिलेंडरों का वितरण अधिक व्यवस्थित, सरल और समयबद्ध तरीके से किया जाएगा, ताकि उपभोक्ताओं को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही गैस बुकिंग, आपूर्ति में विलंब, नए कनेक्शन, केवाईसी, सब्सिडी तथा गैस

एजेंसी से जुड़ी अन्य समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए विशेष समाधान शिविर भी आयोजित किया जाएगा।नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. संदीप जैन ने कहा कि आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना परिषद की प्राथमिक जिम्मेदारी है। गैस वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सुचारु बनाने के लिए एजेंसी के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।वहीं, सत्कार गैस एजेंसी के संचालक गुरमीत सिंह होरा ने भरोसा दिलाया कि समाधान शिविर के माध्यम से उपभोक्ताओं की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एजेंसी नगरवासियों को बेहतर और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।इस पहल से नगर के सभी 17 वार्डों के उपभोक्ताओं को गैस वितरण संबंधी समस्याओं से राहत मिलने और सेवाओं की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।

अभनपुर में बाबा महाकाल की भव्य पालकी यात्रा, श्रद्धालुओं का उमड़ा जनसैलाब

अभनपुर। सावन माह के पावन अवसर पर शनिवार को अभनपुर में श्री महाकाल जन सेवा समिति के तत्वावधान में बाबा महाकाल की भव्य पालकी यात्रा पूरे धार्मिक उत्साह, श्रद्धा और वैदिक विधि-विधान के साथ निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ शीतला माता मंदिर से पूजा-अर्चना के बाद हुआ, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। पालकी यात्रा में बाबा महाकाल की आकर्षक झांकी श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बनी रही। यात्रा के दौरान डमरू दल, धुमाल, डीजे और ÷हर-हर महादेव÷ के जयघोष से पूरा नगर शिवमय हो गया। श्रद्धालु भक्ति गीतों पर नाचते-गाते हुए बाबा महाकाल की पालकी के साथ आगे

बढ़ते रहे।यात्रा मार्ग में विभिन्न सामाजिक संगठनों, व्यापारियों एवं नगरवासियों द्वारा जगह-जगह महाप्रसादी का वितरण किया गया। कई स्थानों पर पालकी यात्रा का पुष्पवर्षा कर भव्य स्वागत किया गया, जिससे पूरे आयोजन का धार्मिक और सांस्कृतिक वातावरण और भी आकर्षक बन गया।इस वर्ष की पालकी यात्रा में अभनपुर नगर सहित आसपास के गांवों से भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। महिलाओं, युवाओं, बच्चों और बुजुर्गों की बड़ी भागीदारी ने यात्रा को ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान किया। पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखने को मिला।आयोजकों ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा महाकाल की पालकी यात्रा का आयोजन श्रद्धा और भक्ति के साथ किया गया। यात्रा शांतिपूर्ण एवं भक्तिमय वातावरण में संपन्न हुई।

लगातार बारिश से बिगड़े हालात, राहत के लिए खोले गए हीराकुंड डेम के 12 गेट, प्रभावित इलाकों में प्रशासन और ह्ष्ठक्रस्न की टीम अलर्ट मोड पर

महानदी उफान पर पुसौर और सरिया ब्लॉक के कई गांवों में घुसा पानी, सैकड़ों एकड़ खेत डूबे, सब्जी की खेती चौपट

रायगढ़/मूक पत्रिका

प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से महानदी ने भी रौद्र रूप धारण कर लिया है। इस वजह से रायगढ़ जिले के पुसौर ब्लाक एवं सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सरिया क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हुए। शुक्रवार को महानदी अपने तटबंध तोड़ते हुए दर्जन भर से अधिक गांवों में प्रवेश कर गई थी जिसकी वजह से सैकड़ों एकड़ खेत जलमग्न हो गये हैं। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड में आते हुए ऐहितायातन तौर पर सतर्कता बरतने तटवर्ती गांव में मुनादी कराई गई। वहीं पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की टीम को सक्रिय किया गया था तथा राहत शिविरों की साफ सफाई कराकर प्रभावित लोगों को रूकने की व्यवस्था की गई थी। हालांकि बढ़ते जल स्तर को देखते हुए ओड़िसा के हीराकुंड डेम के गेट को खोला गया है जिससे रिहायशी इलाकों तक पानी नहीं पहुंच पाया और धीरे-धीरे महानदी का जल स्तर कम हो रहा है। वहीं खेतों के लबालब होने के कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, खासकर सब्जी उत्पादक किसान अधिकांश तौर पर प्रभावित हुए है। प्रशासन द्वारा फसल नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। विगत तीन-चार दिनों से प्रदेश भर में हो रही बारिश के कारण सभी नदी-नाले उफान पर आ गये हैं। वहीं धमतरी के गंगरेल बांध में

अधिक जलभराव होने के कारण डेम के गेट खोले गये हैं जिससे महानदी में बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई। वहीं सहायक नदियों का भी भारी मात्रा में जल आने के कारण महानदी का जलस्तर काफी बढ़ गया। शुक्रवार की सुबह से ही जलस्तर बढने के कारण रायगढ़ जिले के पुसौर ब्लाक के सूरजगढ़, पडिग़ांव, सिंघपुरी, चंघोरी, बाराडोली, टिनमिनी क्षेत्र तथा सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सरिया क्षेत्र में परसामपुर, लिप्ति, रानीडीह, सुरसी, कोर्रा, पोरथ, ठेंगागुड़ी, नदीगांव, रतनपाली, छोटे नावापारा, बोरिदा, खपरापाली, रायपाली इत्यादि गांवों के सैकड़ों एकड़ खेत जलमग्न हो गये तथा नदी का पानी रिहायशी इलाकों में भी घुसने लगा था। पोरथ में नदी किनारे स्थित मंदिर पुरी तरह डुबान में आ गया था तो वहीं रानीडीह गांव में भी आंशिक रूप से रिहायशी क्षेत्र में पानी घुस गया था।वहीं सूरजगढ़ में भी महानदी का पानी गांव के कुछ घरों को अपनी चपेट में ले लिया था। नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण ग्रामीण जहां संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए रतजगा करने पर मजबूर हो गये थे, वहीं उनके खेतों में पानी भरने से हाने वाले नुकसान को लेकर भी उनके माथे पर चिंता की लकीर उभर आई थी। बताया जा रहा है कि पुसौर ब्लाक सहित सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सरिया क्षेत्र में हजारों एकड़ खेत पानी से लबालब हो गये थे। वहीं लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर था तथा बाढ़ की स्थिति से निपटने पूर्ण रूप से तैयारी कर ली गई थी। वहीं कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी व एसएसपी शशि मोहन सिंह ने भी प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया तथा राहत शिविरों में स्वच्छ पेयजल,भोजन व अन्य आवश्यक सामग्रियों की भरपूर तैयारी रखने के निर्देश अपने नोडल अधिकारियों को दिये। वहीं संभावित बाढ़ के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी अलर्ट रखा गया था।

खोले गये हीराकुंड के 12 गेट-महानदी में लगातार बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए ओड़िशा सरकार के साथ सामंजस्य बनाते हुए जिला प्रशासन ने हीराकुंड डेम के गेट खोलने का निवेदन किया था। वहीं ओड़िशा सरकार की ओर से पहले हीराकुंड डेम के 10 गेट खोले गये थे परंतु इससे पर्याप्त राहत मिलती नजर नहीं आई जिसके बाद दो और गेट खोल कर उपरी हिस्से में पानी के दबाव को कम करने का प्रयास किया गया । इस प्रकार हीराकुंड डेम के कुल 12 गेट खोले गये जिससे काफी राहत मिली और पानी धीरे-धीरे कम होने लगा तब कहीं जाकर ग्रामीणों के साथ ही प्रशासन ने भी राहत की सांस ली। वहीं माना जा रहा है कि उपरी कैचमेंट क्षेत्र मे इसी प्रकार अत्यधिक बारिश हुई तब हीराकुंड के और गेट खोलने की आवश्यकता पड़ सकती है।

खेत हुए पानी से लबालब-महानदी का पानी बढने से तटवर्ती गांवों के हजारों एकड़ खेत लबालब हो गये थे। खेतों में पानी भरने के कारण फसल को भारी नुकसान पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। सरिया और पुसौर क्षेत्र में इस बार कई किसान धान की फसल के बजाए गन्ने की खेती किये हैं ऐसे में उनकी खेती खराब होने की संभावना है। वहीं दुसरी ओर इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में किसान साग सब्जी का भी उत्पादन करते हैं लेकिन बाढ़ ने उनकी मेहनत की गाढ़ी कमाई को खत्म कर दिया है।अधिकांश किसानों ने हाल ही में धान की फसल लगाई गई थी जिससे पौधे काफी छोटे हैं लिहाजा उन्हे बढने के लिए किसानों ने रासायनिक खाद का छिडक़ाव किया था। खेतों में पानी भरने की वजह से खाद भी बह गई लिहाजा जल्द ही बाढ़ का पानी नहीं उतरा तो उन्हे दोहरी मार का सामना करना पड़ सकता है। सरिया क्षेत्र के ग्राम लिप्ती, रानीडीह, नदीगांव इत्यादि गांव अधिक प्रभावित हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि हीराकुंड डेम के गेट खोले जाने के बाद जल स्तर कम हो रहा है, वहीं पुरी तरह से पानी खाली होने के बाद फसल के नुकसानी का आंकलन किया जायेगा।

बाढ़ राहत के लिए प्रशासन ने की तैयारी- महानदी में लगातार बढ़ते जल स्तर को देखते हुए संभावित बाढ़ से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने भी अपनी ओर से पूरी तैयारी कर रखी है। बताया जा रहा है कि यदि पानी रिहायशी इलाकों में घुसता है तो ग्रामीणों को राहत शिविरों में ठहराने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है जिसमें पुसौर ब्लाक के पडिग़ांव, छोटे हरदी, बुनगा और टिनमिनी में राहत शिविर बनाये गये हैं जहां भोजन सहित अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था की गई है।

स्वास्थ्य टीम को भी रखा गया था अलर्ट- रायगढ़ जिले के पुसौर ब्लाक में दर्जन भर महानदी के तटवर्ती गांव बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में हैं। जल स्तर अधिक बढने पर प्रशासन द्वारा यहां कि रहवासियों को सुरक्षित राहत शिविरों में पहुंचाने की व्यवस्था की गई थी। वहीं माटर बोट, गोताखोरों की टीम के अलावा पुलिस, एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की टीम को सक्रिय किया गया था । इसके साथ ही अलग-अलग क्षेत्रों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर स्थिति पर नजर रखी गई।

इन्फिस्टार रिन्यूएबल्स और फिनलैंड की आर्सीप्लग की भागीदारी, भारत में पहली बार आएगी मॉड्यूलर प्लग फ्लो सीबीजी तकनीक

इन्फिस्टार रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड ने फिनलैंड की कंपनी आर्सीप्लग ओय (Arciplug Oy) के साथ एक विशेष जॉइंट वेंचर किया है। इस भागीदारी के तहत भारत के पहले मेक इन इंडिया मॉड्यूलर प्लग फ्लो कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) प्लांट बनाए जाएंगे। इस पहल को देश में क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने और आधुनिक बायोगैस तकनीक उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। दोनों कंपनियों ने साझेदारी में आर्सीस्टार बायोएनर्जी प्राइवेट लिमिटेड नामक नई कंपनी रची है। यह कंपनी 3 टन प्रतिदिन (TPD) से कम क्षमता वाले मॉड्यूलर प्लग फ्लो सीबीजी प्लांट को तैयार करेगी। यह प्लांट कृषि अवशेष, नगर निगम के ठोस कचरे (MSW) और अन्य जैविक कचरे से क्लीन एनर्जी का उत्पादन करेंगे। इस तकनीक को पहले से यूरोप और एशिया के कई देशों में सफलतापूर्वक उपयोग की जा रही है और अब भारत में पहली बार लाई जा रही है। भारत जब आयातित फोसिल फ्यूअल पर निर्भरता कम करने के लिए क्लीन एनर्जी की तरफतेजी से बढ रहा है तब इस टेक्नोलोजी से देश को एनर्जी सिक्योरिटी, क्लायमेट चेन्ज, वेस्ट मेनेजमेन्ट तथा वोटर कन्झर्वेशन की दिशा में व्यवहारिक तथा स्थिर सोल्यूशन्स प्राप्त होंगे। इन मॉड्यूलर प्लांट्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन्हें केवल 4 से 5 महीने में शुरु किया जा सकता है, जबकि पारंपरिक बायोगैस प्लांट को तैयार होने में 12 से 18 महीने का समय लगता है। साथ ही, इस तकनीक में पारंपरिक वेट डाइजेशन सिस्टम की तुलना में अत्यधिक कम पानी का उपयोग होता है, इसमें लगभग 30 प्रतिशत कम फीडस्टॉक की जरूरत होती है और बिजली की खपत भी बहुत कम होती है। इससे प्लांट का चलाने का खर्च घटता है और प्रोजेक्ट आर्थिक रूप से अधिक लाभदायक बनता है। ये मॉड्यूलर प्लांट 100 से अधिक अलग अलग प्रकार के जैविक पदार्थों जैसे नेपियर घास, नगर निगम का कचरा, धान का पुआल, प्रेसमड, कपास का अवशेष, फल एवं सब्जियों का कचरा, पोल्ट्री वेस्ट और मछली अपशिष्ट आदि से बायोगैस तैयार कर सकते हैं। इसलिए इनका उपयोग कृषि, उद्योग और नगर निकायों में आसानी से किया जा सकता है। इस जोईन्ट वेन्चर पर प्रतिक्रिया देते हुए इन्फिस्टार ग्रुप के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक सुहृद वी. साराभाई ने कहा कि भारत को स्वच्छ, आत्मनिर्भर और किफायती एनर्जी सोल्यूशन्स की जरूरत है।

डिस्कवरी ने 'डीक्लासिफाइड: ऑपरेशन सिंदूर' की घोषणा की - भारत के 88 घंटे के मिलिट्री ऑपरेशन की एक अभूतपूर्व झलक

इतिहास की दिशा बदल देने वाले हर निर्णायक क्षण के पीछे कई ऐसे फैसले होते हैं, जो अक्सर लोगों की नज़रों से ओझल रह जाते हैं। इन्हीं अनकहे पहलुओं को सामने लाने के लिए डिस्कवरी ने आज अपनी नई दो-भागों वाली डॉक्यूमेंट्री डीक्लासिफाइड: ऑपरेशन सिंदूर की घोषणा की। यह डॉक्यूमेंट्री देश के सबसे महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों में से एक की दुर्लभ और पहली बार सामने लाई गई अंदरूनी झलक पेश करेगी। यह सीरीज़ 15 अगस्त, 2026 को खास तौर पर डिस्कवरी और डिस्कवरी+ पर दिखाई जाएगी; इसका पहला भाग रात 9 बजे और दूसरा भाग रात 10 बजे प्रसारित होगा। यह अभूतपूर्व डॉक्यूमेंट्री भारत के सैन्य नेतृत्व, जमीनी स्तर पर अभियान में शामिल अधिकारियों, रक्षा विशेषज्ञों और वरिष्ठ पत्रकारों को एक साथ लाती है, जो 88 घंटे तक चले संघर्ष के दौरान पर्दे के पीछे हुई घटनाओं और रणनीतिक फैसलों की विस्तृत जानकारी साझा करते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद की परिस्थितियों से शुरू होकर यह श्रृंखला भारत की प्रतिक्रिया की पूरी कहानी प्रस्तुत करती है। इसमें शुरुआती रणनीतिक विचार-विमर्श, सैन्य तैयारियों से लेकर ऑपरेशन सिंदूर की योजना, शुरुआत और उसे अंजाम देने तक की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से दिखाया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों और अभियान से जुड़े लोगों के अनुभवों के माध्यम से यह डॉक्यूमेंट्री भारत के वॉर रूम और फ्रंटलाइन पर तैनात अधिकारियों एवं सैनिकों की भूमिका को सामने लाती है। साथ ही, यह दो परमाणु-संपन्न देशों के बीच हुए इस संघर्ष की अंदरूनी तस्वीर भी सामने लाती है। अब तक सामने आई जानकारी से आगे बढ़कर, यह डॉक्यूमेंट्री उन अहम घटनाओं और रणनीतिक फैसलों को सामने लाती है, जिनके बारे में अब तक सार्वजनिक तौर पर जानकारी नहीं दी गई थी।

मंदिर के सामने डीजे बजाने के विवाद से कैसे नेपाल में भड़की सांप्रदायिक हिंसा, भारत में चिंता?

काठमांडू, एजेंसी। नेपाल में बीते तीन दिन से हालात तनावपूर्ण हैं। दरअसल, नेपाल के सुंसारी जिले में 27 जुलाई को सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी। तीन दिन में ये तनाव चार अलग-अलग जिलों तक पहुंच गया है। भारतीय सीमा के करीब के नेपाली शहरों में स्थिति सबसे ज्यादा खराब हुई है। अब इस सांप्रदायिक हिंसा पर न सिर्फ नेपाल, बल्कि भारत में भी चिंता जताई जा रही है।

ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर नेपाल में यह सांप्रदायिक हिंसा अचानक कैसे भड़क गई? तनाव भड़कने की वजह क्या रही? कैसे यह तनाव एक के बाद एक शहरों तक पहुंच गया? नेपाल सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए क्या किया है? सियासी दलों ने इस हिंसा पर क्या कहा है? भारत पर नेपाल के इस तनाव का क्या असर पड़ सकता है? आइये जानते हैं...

नेपाल में कैसे अचानक भड़क उठी हिंसा?

नेपाल के सुनसारी जिले के देवानगंज में हुई हालिया सांप्रदायिक हिंसा का तात्कालिक कारण एक

स्थानीय विवाद रहा। हालांकि, पूरी घटना अचानक नहीं भड़की, बल्कि इसकी वजह लंबे समय से पनप रहा धार्मिक अलगाव रहा। 26 जुलाई को कप्तानगंज क्षेत्र में कुछ लोगों ने बिजली के खंभे पर लगे मुस्लिम समुदाय के एक झंडे को हटाकर उसकी जगह हिंदू झंडा लगा दिया। इससे क्षेत्र में तनाव पहले से ही बना हुआ था। इसके बाद रात को कप्तानगंज में एक मंदिर के बाहर तेज आवाज में बज रहे डीजे सिस्टम को लेकर विवाद शुरू हुआ। शुरुआत में दो पक्षों के बीच बहस हुई और देखते ही देखते यह पथराव में बदल गई। इसके बाद जब स्थानीय पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल (एपीएफ) ने बढ़ती भीड़ को तितर-बितर करने के लिए गोलियां चलाईं, तो उसमें ओम प्रकाश मेहता नाम के 24 वर्षीय युवक की मौत हो गई। इस मौत के बाद हिंसा और भड़क गई और इससे पूरा जिला प्रभावित हुआ। प्रशासन को स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कई इलाकों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाना पड़ा।

सांप्रदायिक हिंसा में अब तक कितनी जानें गईं, कितने घायल: इस सांप्रदायिक हिंसा और उससे जुड़ी घटनाओं में अब तक दो लोगों की जान गई है और लगभग 22 से 24 लोग घायल हुए हैं।

सुनसारी जिले के कप्तानगंज (देवानगंज) में हुई हिंसा के दौरान भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षाबलों की ओर से फायरिंग के बाद गोली लगने से 24 वर्षीय ओम प्रकाश मेहता की मौत हो गई।

इसके बाद, जब यह अशांति पड़ोसी सिरहा जिले के गोलबाजार में फैली, तो वहां भी भड़के उपद्रव और कर्फ्यू के बीच एक अन्य व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। देवानगंज की घटना में अलग-अलग रिपोर्टों के अनुसार, लगभग 22 से 24 लोग घायल हुए हैं। इन घायलों में सुरक्षाकर्मी और स्थानीय नागरिक दोनों शामिल हैं। नेपाल पुलिस के 10 जवान, सशस्त्र पुलिस बल के पांच जवान और नौ स्थानीय नागरिक घायल हुए हैं।

ढह चुका है पाकिस्तान का सिस्टम: गृह मंत्री मोहसिन नकवी का कबूलनामा

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने देश की बदहाल स्थिति पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि पाकिस्तान की मौजूदा शासन-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और अब यह देश की चुनौतियों से निपटने में सक्षम नहीं है। इस्लामाबाद में आयोजित पहले 'पाकिस्तान इकोनॉमिक समिट' को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि जिस व्यवस्था में हम रह रहे हैं, वह ढह चुकी है। मानो या न मानो आप इस व्यवस्था को 70 साल से घसीट रहे हैं, और जबकि हम सब लोकतंत्र चाहते हैं, लोकतंत्र के अंदर कई रूप होते हैं। मौजूदा व्यवस्था के जरिए समस्याएं हल नहीं हो सकतीं। ' क्या प्रशासनिक सुधारों से बदलेगी पाकिस्तान की तस्वीर? गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने देश में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक सुधारों की वकालत

की है। उन्होंने नए प्रशासनिक निकायों और नई इकाइयों के गठन पर जोर दिया। नकवी की यह मांग पाकिस्तान के कई प्रमुख राजनीतिक दलों की उस पुरानी मांग से मेल खाती है, जिसमें बेहतर शासन संचालन के लिए देश में अधिक प्रांत बनाने की बात कही जाती रही है। नकवी के इस बयान से साफ है कि पाकिस्तान का शीर्ष नेतृत्व भी अब यह मानने लगा है कि मौजूदा ढर्रे पर देश को आगे चलाना नामुमकिन है। रिकॉर्ड कर्ज का बोझ और विदेशी मुद्रा भंडार का संकट पाकिस्तान इस समय अपने इतिहास के सबसे भीषण आर्थिक दौर से गुजर रहा है। देश का कुल विदेशी कर्ज लगभग 137 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है, जिसमें आईएमएफ का ही 8.8 अरब डॉलर है। यह कुल सरकारी कर्ज जीडीपी का करीब 70% से 80% तक पहुंच गया है। हालत यह है कि पाकिस्तान सरकार के बजट का एक बड़ा हिस्सा (लगभग दो-तिहाई) केवल पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने में ही चला जाता है। देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम बचा है कि वह बिना किसी बाहरी वित्तीय मदद के कुछ महीनों का आयात भी नहीं संभाल सकता। वेंटिलेटर से बाहर निकालने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की शरण में जाने के लिए मजबूर है। आजादी से लेकर अब तक पाकिस्तान 25 बार आईएमएफ से बेलआउट पैकेज (कर्ज) ले चुका है। आईएमएफ की सख्त शर्तों (जैसे टैक्स बढ़ाना, बिजली-ईंधन के दाम बढ़ाना और सब्सिडी खत्म करना) के कारण देश में आम जनता भारी महंगाई झेल रही है। इसके अलावा, सऊदी अरब, चीन और संयुक्त अरब अमीरात जैसे मित्र देशों से बार-बार रोलोवर (पुराने कर्ज की मियाद बढ़ाना) और नकद जमा मांगकर देश का कामकाज चलाया जा रहा है। गृह मंत्री नकवी के बयान का दूसरा पहलू प्रशासनिक नाकामी से जुड़ा है। 70 साल पुराना केंद्रीय ढांचा न तो सही तरीके से टैक्स वसूल पा रहा है।

यूरोप की खुली सीमाओं पर संकट

इतालवी पीएम ने दी शेंगेन समझौते को रद्द करने की धमकी

रोम, एजेंसी। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार असाधारण कदम उठाने के लिए तैयार है। इसमें जरूरत पड़ने पर स्पेन के साथ शेंगेन समझौते को निलंबित करना भी शामिल है। उनका यह बयान स्पेन के स्यूटा क्षेत्र में प्रवासियों की संख्या में अचानक आई बढ़ोतरी के बाद आया है।

मेलोनी ने क्या कहा-क्या कहा?

इतालवी पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि उनकी सरकार सीमा पर बन रहे हालात को देखते हुए चुप नहीं बैठेगी।

उन्होंने कहा कि उच्च स्तरीय बैठकों के फैसले के आधार पर इटली अपनी सीमाओं की रक्षा और लोगों की सुरक्षा के लिए असाधारण कदम उठाने को तैयार है।

उन्होंने खासतौर से स्पेन के साथ खुले सीमा वाले शेंगेन समझौते को निलंबित करने का विकल्प भी बताया।

मेलोनी ने दोहराया कि उनकी सरकार अवैध प्रवासन के खिलाफ सख्त नीति पर कायम है।

उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता सीमाओं की सुरक्षा, मानव तस्करी के गिरोहों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और अवैध प्रवासियों को जल्दी वापस भेजना है। स्यूटा में क्यों बढ़ा संकटत्न उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब स्पेन के स्वायत्त क्षेत्र स्यूटा में सीमा संकट तेजी से बढ़ रहा है। स्यूटा की मोरक्को के साथ जमीनी सीमा लगती है। पोलिटिको के अनुसार, बुधवार से हजारों प्रवासी इस क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। इससे स्थानीय प्रशासन पर भारी दबाव पड़ गया है और सीमा प्रबंधन को लेकर स्पेन के प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज की आलोचना तेज हो गई है।

स्थानीय प्रशासन ने क्या कहा?

स्यूटा के क्षेत्रीय अधिकारियों ने बुधवार को समुद्री मार्गों से

पीएम मेलोनी ने क्या चेतावनी दी?

पीएम मेलोनी ने एक्स पर लिखा कि स्यूटा से सामने आ रही तस्वीरें इस बात का स्पष्ट प्रमाण हैं कि अनियंत्रित अवैध प्रवासन यूरोप की सीमाओं की सुरक्षा के लिए वास्तविक खतरा है। मेलोनी ने बताया कि उन्होंने इटली के गृह मंत्री मत्तेओ प्यान्तेदोसी से सीधे बात की है और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों की बैठक बुलाई गई है, ताकि औपचारिक जवाबी कार्रवाई पर फैसला किया जा सके।

लगातार पहुंच रहे प्रवासियों को लेकर चेतावनी जारी की। स्यूटा के क्षेत्रीय प्रमुख जुआन जीसस विवास ने स्थिति को 'पूरी तरह मानवीय और सामाजिक आपातकाल' बताया। उन्होंने मैड्रिड की केंद्र सरकार से तुरंत दखल की मांग की।

स्पेन सरकार पर क्यों बढ़ा दबाव?

प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने गुरुवार को एक्स पर कहा कि उनकी सरकार मोरक्को के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है, ताकि स्थिति को सामान्य किया जा सके। उन्होंने जल्द सरकारी कार्रवाई का भी भरोसा दिया। सांचेज पर राजनीतिक दबाव उस समय और बढ़ गया, जब स्पेन के सुप्रीम कोर्ट ने समुद्र के रास्ते आने वाले प्रवासियों को तुरंत वापस भेजने पर रोक लगाने वाला फैसला दिया। इस संकट के कारण प्रधानमंत्री की देश के भीतर भी तीखी आलोचना हो रही है।

बदल रही है खूबसूरती की परिभाषा: 80+ महिलाएं बन रही हैं फैशन की नई पहचान, अलोर पत्रिका ने हटाया बुढ़ापा शब्द

वाशिंगटन/पेरिस/लंदन, एजेंसी। सफेद बाल, चेहरे पर अनुभवों की झुर्रियां व आंखों में बेमिसाल चमक... फैशन व सौंदर्य की दुनिया में अब खूबसूरती की परिभाषा बदल रही है। 20 और 30 के दशक के युवाओं पर केंद्रित रहने वाली ग्लैमर इंडस्ट्री अब 80 की उम्र पार महिलाओं (ऑक्टोजेनेरियन) की जीवंतता, उनकी ऊर्जा और अद्वितीय स्टाइल की मुरीद हो चुकी है। 80 की उम्र में भी 40 की ऊर्जा से जीवन जीने वाली इन महिलाओं को वैश्विक हस्तियां व पत्रकार दुनिया के सामने ला रहे हैं।

ठ्ठ महिला अधिकारों और समाज पर काम करने वाली मारिया हिनोहोसा और नाओमी वुल्फ जैसी चर्चित हस्तियों ने जहां इस उम्र की महिलाओं के योगदान को रेखांकित किया, वहीं फैशन एवं ब्यूटी पत्रकारिता की दुनिया में सुजैन रोवान क्रोके और एलिसन कार्ल जैसी वरिष्ठ संपादकों ने उम्रदराज महिलाओं की वास्तविक और मौलिक खूबसूरती पर व्यापक स्तरीय काम किया है। पूर्व मुख्य संपादक मिशेल ली ने मैग्जीन में एंटी-एजिंग (बुढ़ापा) शब्द का उपयोग ही रोक दिया। प्रसिद्ध फैशन-स्टाइल विशेषज्ञ अरी सेथ कोहेन ने बुजुर्ग महिलाओं का स्टाइल ब्लॉग बना उम्रदराज महिलाओं को पहचान दी।

उम्रदराज महिलाओं के लिए लॉरियल पेरिस कंपनी एज परफेक्ट श्रृंखला लेकर आई है, जिसमें 60 से

80 वर्ष तक की महिलाओं को लिए उत्पाद डिजाइन किए गए हैं। कुछ लग्जरी ब्रांड कंपनियों ने पौष्टिक तेलों सेरामाइड्स और पेप्टाइड्स से भरपूर नाइट रीस्टोरेटिव क्रीम और सीरम बनाए हैं। पेंटीन और लॉरियल कंपनियां उम्रदराज महिलाओं के बालों की सुरक्षा के लिए उत्पाद लेकर आई हैं। यही नहीं, टॉमी हिलफिगर और टारगेट जैसे बड़े फैशन हाउस ऐसे कपड़े डिजाइन कर रहे हैं जिनमें बटन की जगह मैग्नेट (चुंबक) और वेल्क्रो का उपयोग होता है, ताकि 80+ उम्र की महिलाएं बिना किसी की मदद के आसानी से स्टाइलिश कपड़े पहन सकें। दुनिया का सबसे प्रसिद्ध और क्रांतिकारी प्रोजेक्ट एडवांस्ड स्टाइल को माना जाता है। इसकी शुरुआत प्रसिद्ध फैशन व स्टाइल विश्लेषक अरी सेथ कोहेन ने की। उन्होंने न्यूयॉर्क, लंदन व टोक्यो तक की सड़कों पर 70, 80 और 90 से अधिक वर्ष की ऐसी महिलाओं को तलाशा, जिनका फैशन सेंस किसी युवा मॉडल को भी मात दे दे। कोहेन ने साबित किया कि स्टाइल उम्र की मोहताज नहीं होती। इन महिलाओं का पहनावा, रंगों का चुनाव और जीवन जीने का अंदा अद्वितीय रहा है।

इराक ने कहा- हमें नहीं थी खबर

क्या बिना इजाजत हुआ बगदाद पर हमला: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा झूठा

बगदाद, एजेंसी। इराक की जमीन पर हाल ही में हुए अमेरिका और सऊदी अरब के साझा हवाई हमलों के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बहुत बढ़ गया है। इन हमलों को लेकर इराकी सरकार ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि ये हमले इराकी सरकार के साथ तालमेल बिठाकर किए गए थे। हालांकि, इराक सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति के इस दावे को पूरी तरह से नकार दिया है। इराक ने कहा है कि उसने अपनी जमीन पर किसी भी हमले की कोई मंजूरी नहीं दी थी और न ही उसे इसकी कोई पूर्व जानकारी थी। अल-आबोदी ने इस पूरे मामले पर बयान जारी किया है। उन्होंने मीडिया को बताया कि बगदाद ने अपनी सीमाओं के भीतर किसी भी स्थान या समूह को निशाना बनाने की अनुमति नहीं दी थी। उन्होंने कहा कि सरकार को इन सैन्य कार्रवाइयों के बारे में पहले से कोई खबर नहीं थी। इराक ने बुधवार को ही इन हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की थी और अब ट्रंप के बयान का

सीधा खंडन कर दिया है। इराक का कहना है कि बिना बताए किया गया यह हमला उसकी संप्रभुता का सीधा उल्लंघन है। इस हवाई हमले में ईरान समर्थित ग्रुप 'पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस' (पीएमएफ) के कम से कम 20 लड़ाकों की जान गई है। ट्रंप का दावा खारिजः इराक ने कहा कि अमेरिका ने हमले से पहले कोई बातचीत नहीं की थी और न ही कोई अनुमति ली थी। पीएम का दौरा रद्दः बढ़ते तनाव को देखते हुए इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल-सुदानी ने अपना सऊदी अरब का दौरा टाल दिया है। सऊदी से सबूत की मांगः इराक ने सऊदी अरब से उन दावों के पक्के सबूत मांगे हैं, जिनमें कहा गया था कि उस पर हमले इराक से हुए। इराक का कड़ा रुखः इराक ने साफ किया है कि वह न तो अपनी जमीन से किसी पर हमला होने देगा और न ही विदेशी सैन्य दखल सहेगा। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने आरोप लगाया था कि सोमवार और मंगलवार को उनकी राजधानी रियाद और कई जरूरी जगहों पर ड्रोन हमले किए गए थे। सऊदी का दावा था कि ये ड्रोन इराक की सीमा के भीतर से दागे गए थे। हालांकि, इराक ने सऊदी के इन आरोपों पर कड़ी आपत्ति जताई है और उनसे इसका सबूत पेश करने को कहा है। इराकी पीएम के प्रवक्ता सबाह अल-नुमान ने कहा कि सऊदी अरब ने अभी तक अपने आरोपों के समर्थन में कोई दस्तावेज या सबूत नहीं दिया है।

मोरक्को की सीमा तोड़कर स्पेन में घुसे हजारों प्रवासी: नौ की मौत, मचा हड़कंप

स्यूटा, एजेंसी। मोरक्को से हजारों प्रवासी गुरुवार को स्पेन के छोटे से स्वायत्त क्षेत्र स्यूटा में पहुंच गए। सीमा पार करते समय मची अफरा-तफरी में नौ लोगों की मौत भी हो गई। इसके बाद स्थानीय अधिकारियों ने स्पेन सरकार से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने और सीमा पर स्थिति संभालने के लिए सेना भेजने की मांग की। स्पेन के गृह मंत्रालय ने कहा कि वह अपने नागरिकों की सुरक्षा और देश की सीमा की रक्षा सुनिश्चित करेगा। हालांकि, सरकार प्रवास से जुड़ी चिंताओं को लेकर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित नहीं कर सकती।

राशिद सबीही स्यूटा में स्पेन की सिविल गार्ड के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन के प्रमुख हैं। उन्होंने बताया कि स्थिति पूरी तरह अराजक है। उन्होंने कहा, सटीक संख्या बताना संभव नहीं है, लेकिन हजारों प्रवासी सीमा पार कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सीमा की स्थिति पूरी तरह बिगड़ चुकी है।

उत्तरी मोरक्को में मानवाधिकार संगठन के सदस्य अशरफ मैमौनी ने स्थिति को 'असाधारण' बताया। उन्होंने कहा, आज सुबह ताराजल सीमा को असामान्य हालात में खोला गया और लोग वहां से अंदर आ गए।

वीडियो फुटेज में दिखाया गया कि बड़ी संख्या में लोग

ताराजल समुद्र तट के किनारे बने तटबंधों से होते हुए स्थानीय सड़कों पर पहुंच रहे थे। इनमें ज्यादातर मोरक्को के नागरिक थे। ज्यादातर युवा पुरुष दिखाई दे रहे थे, लेकिन महिलाओं और बच्चों वाले परिवार भी शामिल थे। कुछ लोगों ने एसोसिएटेड प्रेस के लिए काम कर रहे एक स्वतंत्र फोटोग्राफर को देखकर 'विवा एस्पाना' (स्पेन जिंदाबाद) के नारे भी लगाए। अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि इतनी बड़ी संख्या में प्रवासियों के स्यूटा पहुंचने की वजह क्या थी।

स्पेन और मोरक्को की सीमा पर यह तनाव बुधवार को छोटे से स्पेनिश क्षेत्र में पहुंचने की कोशिश कर रहे प्रवासियों की संख्या बढ़ने के बाद बढ़ा। इनमें से ज्यादातर लोग समुद्र में तैरकर स्यूटा पहुंचने की कोशिश कर रहे थे।

सबीही और मोरक्को तथा स्यूटा के सामाजिक कार्यकर्ताओं के अनुसार, बुधवार को समुद्र के रास्ते स्यूटा पहुंचने की कोशिश में तीन लोगों की मौत हो गई। मोरक्को के अधिकारियों ने इस सीमा पार करने की घटना पर सार्वजनिक रूप से कोई बयान नहीं दिया है।

स्पेन के गृह मंत्रालय ने कहा कि मोरक्को सरकार स्थिति संभालने में स्पेन के साथ 'करीबी सहयोग' कर रही है। मंत्रालय ने बताया कि मोरक्को की पुलिस सीमा पार करने की कोशिश कर रहे कई लोगों को रोक रही है। दोनों देशों ने मिलकर काम करने पर सहमति जताई है, ताकि स्यूटा में अवैध रूप से दाखिल हुए सभी लोगों को जल्द से जल्द वापस भेजा जा सके। स्पेन के गृह मंत्री फर्नांडो ग्रांडे-मार्लास्का शुक्रवार को स्थिति का जायजा लेने के लिए स्यूटा जाएंगे।

स्यूटा के अधिकारियों ने पहले प्रवासियों की बढ़ती संख्या को इस महीने की शुरुआत में आए स्पेन के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जोड़ा था। इस फैसले के तहत समुद्र के रास्ते स्पेन पहुंचने वाले प्रवासियों को बिना कानूनी प्रक्रिया पूरी किए तुरंत वापस नहीं भेजा जा सकता। हालांकि, जमीन के रास्ते सीमा पार करने वालों पर यह नियम लागू नहीं होता। जैसे, सीमा पर लगी बाड़ को पार करके आने वाले लोगों को अलग नियमों के तहत रोका जाता है। हालांकि, मोरक्को के कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस फैसले को प्रवासियों की बढ़ती संख्या की वजह मानने पर सवाल उठाया। उनका कहना था कि ज्यादातर प्रवासियों को ऐसे कानूनी फैसलों की जानकारी भी नहीं होगी। बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश या अपने देशों में हिंसा से बचने के लिए यूरोप जाने वाले प्रवासियों के लिए स्पेन एक प्रमुख प्रवेश मार्ग है। उत्तरी अफ्रीका के तट पर स्थित स्यूटा पहुंचने के लिए प्रवासी अक्सर मोरक्को के फनीदेक शहर से तैरकर आते हैं।

नकली पनीर, मक्खन, क्रीम और पैकेजिंग पर 1 वर्ष के लिए बै, नकली दुग्ध उत्पाद बनाने वालों के खिलाफछत्तीसगढ़ सरकार की कार्यवाही

ओरिजनल दूध से बने उत्पाद ग्राहकों के सेहत के लिए उपयुक्त

सारंगढ़-बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा राजपत्र में 31 जुलाई 2026 से जारी अधिसूचना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की संपूर्ण भौगोलिक सीमा, जिसमें जिला सारंगढ़- बिलाईगढ़ भी शामिल है, में अमानकीकृत डेयरी एनालॉग (एनालॉग पनीर) तथा ऐसे गैर-दुग्ध उत्पाद जो दूध उत्पाद के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, के निर्माण, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण एवं विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है।यह निर्णय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 18 एवं 30 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए लिया गया है। विभागीय परीक्षण, प्रयोगशाला विश्लेषण एवं जोखिम

मूल्यांकन में यह पाया गया कि कुछ उत्पाद वास्तविक दूध से निर्मित नहीं होने के बावजूद पनीर, क्रीम, मक्खन अथवा अन्य दुग्ध उत्पादों के रूप में उपभोक्ताओं के समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे थे, जिससे उपभोक्ता भ्रमित हो सकते हैं तथा उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है। आदेश के अनुसार ऐसे सभी उत्पाद प्रतिबंधित रहेंगे जो वास्तविक दुग्ध उत्पाद नहीं हैं तथा जिनमें दूध के स्थान पर वनस्पति वसा, वनस्पति तेल अथवा अन्य गैर-दुग्ध अवयवों का उपयोग किया गया हो या जिनकी लेबलिंग, पैकेजिंग अथवा प्रस्तुति उपभोक्ताओं को वास्तविक दुग्ध उत्पाद होने का भ्रम उत्पन्न करती हो।हालांकि, फ्रोजन डेज़र्ट, प्रोसेस्ड चीज़ एवं मिक्स्ड फैट स्प्रेड जैसे विधिवत मानकीकृत उत्पाद इस प्रतिबंध के दायरे में शामिल नहीं हैं। यह प्रतिबंध राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष तक अथवा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में अंतिम नियम जारी किए जाने तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगा। ओरिजनल दूध से बने उत्पाद ग्राहकों के सेहत के लिए उपयुक्त है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ द्वारा सारंगढ़ के होटल और ढाबा में नकली दूध उत्पाद का जांच किया गया है और जिले के सभी खाद्य कारोबार संचालकों, डेयरी उत्पाद निर्माताओं, थोक एवं फुटकर विक्रेताओं से शासन के निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने की अपील की गई है।

गरीबों के राशन में कथित कटौती पर गरमाई सियासत, दोषियों पर कार्रवाई की मांग

उप नेता प्रतिपक्ष लखेश्वर बघेल ने राजपुर पीडीएस मामले की उच्चस्तरीय जांच की उठाई मांग

बस्तर /मूक पत्रिका

बस्तर विधायक एवं छत्तीसगढ़ विधानसभा के उप नेता प्रतिपक्ष लखेश्वर बघेल ने बस्तर विकासखंड के ग्राम पंचायत राजपुर की उचित मूल्य दुकान में राशन वितरण में कथित अनियमितता को गंभीर मामला बताते हुए उच्चस्तरीय जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बघेल ने आरोप लगाया कि राजपुर पंचायत के करीब 600 हितग्राहियों को निर्धारित 35 किलो चावल के स्थान पर केवल 31 किलो चावल दिए जाने की शिकायत सामने आई है। उनका कहना है कि ग्रामीणों द्वारा बनाए गए वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन पर 35 किलो और दूसरी मशीन पर 31 किलो वजन दिखाई देने का दावा किया गया है। यदि यह तथ्य सही है, तो यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में गंभीर अनियमितता और गरीबों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ का मामला है।

उन्होंने कहा कि यह घटना खाद्य विभाग और जिला प्रशासन की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है। यदि उचित मूल्य दुकानों का नियमित निरीक्षण और इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनों का समय-समय पर परीक्षण किया जाता, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती।

उप नेता प्रतिपक्ष ने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कर दोषी राशन विक्रेता, संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही प्रभावित सभी हितग्राहियों को उनका पूरा राशन तत्काल उपलब्ध कराया जाए तथा जिले की सभी उचित मूल्य दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनों की विशेष जांच कराई जाए।

बघेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी गरीबों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और यदि दोषियों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तथा प्रभावित परिवारों को पूरा राशन नहीं मिला, तो कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि गरीबों के हक पर किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

व्हाट्सएप से ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाला सटोरिया गिरफ्तार, सिटी कोतवाली व साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई

कांकेर/मूक पत्रिका

विक्रम ठाकुर/:- उत्तर बस्तर कांकेर पुलिस द्वारा जिले में जुआ, सट्टा और अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना सिटी कोतवाली और साइबर सेल की टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मोबाइल और व्हाट्सएप के जरिए घूम-घूमकर सट्टा खिलाने वाले एक आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से मोटरसाइकिल, मोबाइल और नगदी सहित कुल ?46,000 की संपत्ति जब्त की गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश साहू के मार्गदर्शन तथा अनुविभागीय

अधिकारी मोहसिन खान के पर्यवेक्षण में अपराध नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा है। दिनांक 1 अगस्त 2026 को गश्त के दौरान पी.एस.आई. प्रज्ञा पैकरा को मुखबिर से सूचना मिली कि गोविंदपुर खेल मैदान के पास एक व्यक्ति अपनी बाइक से घूम-घूमकर मोबाइल पर व्हाट्सएप के माध्यम से वरली मटका, कल्याण और राजधानी नाइट का सट्टा संचालित कर रहा है। पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और भागने का प्रयास कर रहे संदेही को दबोच लिया। पुराने आपराधिक रिकॉर्ड का खुलासा पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम सद्दाम हुसैन (32 वर्ष), निवासी बागोडार, थाना सिटी कोतवाली कांकेर बताया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से सट्टा संचालन में प्रयुक्त 2 मोबाइल (कीमत ?11,000), एक प्लेटिना मोटरसाइकिल (क्रमांक छ्त्त 05 ,त्र 1826, कीमत ?30,000) और ?5,000 नगद बरामद हुए। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपी सद्दाम हुसैन के खिलाफवर्ष 2013 में धारा 304 भादवि का मामला दर्ज है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 256/2026 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 7(1) एवं भारतीय न्याय संहिता की धारा 112 (2) के तहत अपराध दर्ज किया है। मामला अजमानतीय होने के कारण आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा (जेल) में भेज दिया गया है।

भारतीय टीम में हुआ रायगढ़ जिले के तीन ताइक्कांडो खिलाडियों का चयन

थाईलैंड में 9वें हीरोज़ कप इंटरनेशनल चैंपियनशिप में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व

रायगढ़/मूक पत्रिका

जिले के लिए गर्व का विषय है कि जिले के तीन ताइक्कांडो खिलाडियों का चयन हुआ है। वहीं इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए वीनर्स ताइक्कांडो अकादमी ने बताया कि चयनित खिलाडियों में एशियन मेडलिस्ट ऋषि सिंह जो स्वंय भी एक कोच भी है। रिषभ सिंह ठाकुर एवं आनिया सिंह का चयन 9वें हीरोज़ कप इंटरनेशनल ताइक्कांडो चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय टीम में हुआ है। तीनों खिलाड़ी विगत 29 जुलाई को भारतीय दल के साथ नई दिल्ली से थाईलैंड के लिए रवाना हुए। यह प्रतियोगिता विगत 31जुलाई से 3 अगस्त 2026 तक थाईलैंड में

आयोजित होगी, जिसमें तीनों खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।वहीं इनका शानदार चयन होने से एसएसपी शशि मोहन सिंह ने तीनों खिलाडियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएँ दी। एशियन मेडलिस्ट ऋषि सिंह ठाकुर सीनियर पुरुष 80 किग्रा भार वर्ग में हुआ है जो ताइक्कांडो से 14 वर्षों से जुड़े हैं। ताइक्कांडो एवं किकबॉक्सिंग में 8 बार के राष्ट्रीय पदक विजेता एशियन चैंपियनशिप में भारत के लिए पदक जीत चुके हैं।

वर्तमान में विनर्स ताइक्कांडो अकादमी, पुलिस लाइन रायगढ़ में मुख्य प्रशिक्षक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। वहीं रिषभ सिंह ठाकुर विगत 2 वर्षों से विनर्स अकादमी में प्रशिक्षणरत हैं जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर लगातार पदक विजेता, जयपुर में आयोजित डब्लूडब्लूएसएल ताइक्कांडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर भारतीय टीम में स्थान पक्का किया। इसी तरह आनिया सिंह ङ्क सब-जूनियर बालिका -20 किग्रा भार वर्ग में हुआ है जो डब्लूडब्लूएसएल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता व छत्तीसगढ़ राज्य चैंपियनशिप एवं मथुरा में आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक विजेता और रायगढ़ की पहली सब-जूनियर अंतरराष्ट्रीय महिला ताइक्कांडो खिलाड़ी बनने जा रही हैं।

खेल जगत में खुशी की लहर

तीनों खिलाडियों के चयन से पूरे रायगढ़ एवं छत्तीसगढ़ में हर्ष का माहौल है। सभी खेल प्रेमी इन तीनों खिलाडियों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। वहीं खेल प्रेमियों को विश्वास है कि तीनों खिलाड़ी थाईलैंड में शानदार प्रदर्शन कर भारत, छत्तीसगढ़ और रायगढ़ का नाम अंतरराष्ट्रीय मंच पर रोशन करेंगे।

प्रतिभावान विद्यार्थियों का हुआ सम्मान, विधायक दीपेश साहू ने दी विकास कार्यों की सौगात

बेमेतरा/मूक पत्रिका

ग्राम पंचायत बहेरा-पेण्ड्री में जिला स्तरीय प्रतिभावान छात्र-छात्रा सम्मान समारोह 2026 का आयोजन उत्साहपूर्वक किया गया। समारोह में कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं एवं 12वीं के लगभग 200 प्रतिभावान छात्र-छात्राओं का सम्मान कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बेमेतरा विधायक दीपेश साहू ने सम्मानित विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि शिक्षा ही समाज और राष्ट्र के विकास का सबसे मजबूत आधार है।

उन्होंने विद्यार्थियों से निरंतर मेहनत कर अपने परिवार, गांव और जिले का नाम रोशन करने का आह्वान किया। इस अवसर पर विधायक ने ग्राम पंचायत बहेरा के विकास के लिए आंगनबाड़ी भवन, नहर निर्माण सहित विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम के मुख्य आयोजक हिरऊ कुमार जांगड़े को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम के

दौरान पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए 100 पौधों का वृक्षारोपण भी किया गया।कार्यक्रम का आयोजन हिरऊ कुमार जांगड़े, मनीशंकर दिवाकर, संदीप टंडन, पवन बघेल, नेतराम कोशले, आत्मानंद सारथी एवं जयकरण मीरे सहित ग्राम पंचायत बहेरा-पेण्ड्री के जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों के सहयोग से किया गया।समारोह में भारतीय किसान संघ छत्तीसगढ़ की प्रदेश महिला प्रमुख श्रीमती अदिति कश्यप, पीसीएसएस के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भुवादास जांगड़े, साहू समाज के जिलाध्यक्ष नारद साहू, पीसीएसएस बेमेतरा महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष श्रीमती मैना देवी मांडले, कृषि वैज्ञानिक डॉ. प्रांजल तिवारी, चंद्रशेखर खरे, रामनारायण पात्रे, श्रीमती कलश मांडले, पंच आरती बघेल, धनेश साहू, सरपंच पति पंचराम साहू, कस्तूर साहू, भारतीय किसान संघ के मीडिया प्रभारी ईश्वरी घृतलहरे, जुगेश बंजारे सहित ग्राम पंचायत के सरपंच, पंच एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने सभी अतिथियों, सम्मानित विद्यार्थियों एवं ग्रामवासियों का आभार व्यक्त करते हुए शिक्षा और सामाजिक विकास के ऐसे आयोजनों को निरंतर जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया।

गिरसाङ्ककिसड़ा मार्ग पर गड्ढे, डामर उखड़ा, ग्रामीणों में नाराजगी, स्वतंत्र तकनीकी जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग

करोड़ों खर्च लेकिन सड़क ध्वस्त, पहली बारिस, गिरसा- किसड़ा मार्ग

सरसींवा (सारंगढ़-बिलाईगढ़)/मूक पत्रिका

कभी कीचड़ और धूल से परेशान रहने वाले गिरसाङ्ककिसड़ा मार्ग के ग्रामीणों ने जब नई सड़क बनते देखी तो लगा कि वर्षों की परेशानी अब खत्म हो गई। लगभग 4 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 12ङ्क13 किलोमीटर लंबी सड़क क्षेत्रवासियों के लिए विकास की नई उम्मीद लेकर आई थी। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी। सड़क बनने के महज 6ङ्क7 महीने बाद ही इसकी हालत देखकर लोग हैरान हैं। पहली ही बारिश ने सड़क की मजबूती की असलियत सामने ला दी है। जगह-जगह डामर उखड़ चुका है, गहरे गड्ढे बन गए हैं और उनमें पानी भर गया है। ऐसा लग रहा है मानो सड़क वर्षों पुरानी हो, जबकि इसे बने अभी कुछ ही महीने हुए हैं।

सवाल यह है कि क्या करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद सड़क इतनी कमजोर बनाई गई कि पहली ही बारिश में जवाब दे गई? यदि निर्माण कार्य पूरी गुणवत्ता और तकनीकी मानकों के अनुरूप हुआ होता, तो इतनी कम अवधि में सड़क की यह दुर्दशा शायद ही देखने को मिलती। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण के दौरान गुणवत्ता की अनदेखी की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि यदि निर्माण एजेंसी और संबंधित विभाग के अधिकारियों ने समय-समय पर प्रभावी निरीक्षण किया होता, तो आज यह स्थिति नहीं बनती। लोगों का कहना है कि सड़क पर बने ये गड्ढे केवल टूटी हुई सड़क नहीं, बल्कि निर्माण व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह मार्ग रोजाना दोपहिया, चारपहिया और भारी वाहनों के आवागमन का प्रमुख रास्ता है। सड़क पर बने गड्ढे किसी भी समय दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते मरम्मत नहीं कराई गई तो आने वाले दिनों में सड़क की स्थिति और भी खराब हो सकती है।

अब क्षेत्रवासियों की मांग है कि पूरे सड़क निर्माण की स्वतंत्र तकनीकी जांच कराई जाए, गुणवत्ता की जांच हो, यदि कहीं अनियमितता या लापरवाही पाई जाए तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और सड़क की तत्काल मरम्मत कराई जाए। करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद भी यदि सड़क पहली ही बारिश में टूटने लगे, तो यह केवल एक सड़क का मामला नहीं, बल्कि जनता के टैक्स के पैसे के उपयोग और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर उठता एक बड़ा सवाल है। इसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है ताकि वास्तविक कारण सामने आ सके।

कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू ने युवाओं को दिलाई नशा मुक्ति संकल्प

प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन किया नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ

सारंगढ़ बिलाईगढ/मूक पत्रिका

भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय तथा माय भारत के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को ÷नशा मुक्त युवाङ्कविकसित भारत संकल्प अभियान÷ का शुभारंभ कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर के युवाओं को ऑनलाइन संबोधित करते हुए नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प दिलाया तथा युवाओं से नशे के विरुद्ध जनआंदोलन खड़ा करने का आह्वान किया।युवाओं को नशे की प्रवृत्ति से दूर रखकर स्वस्थ, जागरूक एवं जिम्मेदार नागरिक बनाने के उद्देश्य से सारंगढ़-

बिलाईगढ़ जिले में इस अभियान का कार्यक्रम शासकीय पंडित लोचन प्रसाद पांडेय महाविद्यालय सारंगढ़ में किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू, डिप्टी कलेक्टर डॉ. वर्षा बंसल, जिला स्तरीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि, महाविद्यालय एवं विद्यालय के छात्र-छात्राएं, एनएसएस, एनसीसी, खेल संघ के सदस्य तथा बड़ी संख्या में युवा उपस्थित रहे। सभी ने प्रधानमंत्री के संबोधन का श्रवण किया और नशा मुक्त भारत के संकल्प को दोहराया। कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू ने उपस्थित सभी युवाओं, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नशा मुक्ति की सामूहिक शपथ दिलाई। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक छात्र-छात्रा माय भारत ऐप पर अपना पंजीयन अवश्य कराएं और राष्ट्र निर्माण की विभिन्न गतिविधियों से जुड़ें। उन्होंने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और नशे से दूर रहकर ही विकसित भारत के निर्माण में अपनी प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं।कलेक्टर ने कहा कि जिला प्रशासन के नेतृत्व में समाज कल्याण विभाग सहित विभिन्न विभागों के सहयोग से नशा मुक्ति के लिए लगातार जनजागरूकता अभियान संचालित किए जा रहे हैं। युवाओं की सक्रिय भागीदारी से ही इस अभियान को मूर्त रूप दिया जा सकता है। इस कार्यक्रम में खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग की सक्रिय सहभागिता रही।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक आशिष कुमार कंठले द्वारा कलयुग का भारत द्वारा अग्रदूत कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, भाजपा कार्यालय के पास, रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)-492001 से मुद्रित एवं वार्ड नंबर 18 बाजार पारा बेमेतरा पोस्ट व जिला बेमेतरा छ.ग. पिन कोड 491335 से प्रकाशित । संपादक आशिष कुमार कंठले समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार मो. नं. 7999238079, 7828658259, समस्त विवादों का निपटारा बेमेतरा न्यायालय होगा।